www.hindmatamirror.com • वर्ष: 12 • अंक: 218 • ठाणे, मंगलवार 5 मई, 2026 • पेज: 8 • मूल्य: 2 रुपए hindmatamirror1@gmail.com

RNI. NO. MAHHIN/2011/43060

दैनिक हिंदमाता मिरर

पैनी नजर, पुख्ता खबर

राधा का टी-20 विश्वकप में चयन से बल्ले और गेंद से सुधार : तनुजा कंवर

पेज 8

कान 2026 में एक बार फिर चमकेंगी जैकलीन फर्नांडिस

8 पेज

पश्चिम बंगाल में भाजपा को प्रचंड बहुमत, विजय पथ पर तमिलनाडु, केरल में सत्ता का यू-टर्न

सुप्रभात

यदि परिस्थिति अनुकूल है तो सीधे अपने ध्येय की ओर चलो, लेकिन यदि परिस्थितियां अनुकूल न हों तो उस मार्ग का अनुसरण करो जिसमें सबसे कम बाधा आने की संभावना हो। - संत तिरुववल्लुवर

मौसम का मिजाज

सूर्यास्त (5 मई) 7:03 बजे, सूर्योदय (6 मई) 6:08 बजे, **तापमान:** 31 डिग्री से. (धूप खिली रहेगी।)

भारतीय राजनीति में वामपंथ का अंत!

50 साल में पहली बार किसी भी राज्य में नहीं होगी लेफ्ट सरकार

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

भारतीय राजनीति में अपनी खास विचारधारा और मजबूत पकड़ के लिए मशहूर वामपंथी दल आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ताजा चुनावी रुझान बताते हैं कि पिछले 50 सालों में यह पहली बार होगा कि जब देश के किसी भी राज्य में वामपंथियों की सरकार नहीं होगी। केरल, जो इनका सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था लेकिन 2026 के चुनावी नतीजे अब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब उनके हाथ से यह आखिरी किला भी खिसक रहा है।

कैसे हुई पतन की शुरुआत?

वामपंथ के इस पतन के पीछे कई ऐतिहासिक कारणों को जिम्मेदार माना जाता है। 1996 में, जब सीपीआई-एम के दिग्गज नेता ज्योति बसु प्रधानमंत्री बनने के बेहद करीब थे तब उनकी पार्टी के पोलित ब्यूरो ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था जिसे बसु ने खुद ही उसे ऐतिहासिक भूल करार दिया था। साल 2008 तक वामपंथी दल राष्ट्रीय राजनीति में इतने प्रभावशाली थे कि मनमोहन सिंह सरकार उनकी मर्जी पर टिकी थी लेकिन परमाणु समझौते के मुद्दे पर समर्थन वापस लेना उनके प्रभाव को कम करने की शुरुआत साबित हुई।

स्वर्णकाल से शून्य की ओर

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1952 के पहले चुनाव में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी और 1957 में केरल में दुनिया की पहली ऐसी कम्युनिस्ट सरकार बनाई जिसे जनता ने वोट देकर चुना था। अब केरलम में हार से सत्ता से बाहर हो गई है।

बीजेपी की सुनामी!

16 राज्यों में भाजपा सरकार, कांग्रेस सिर्फ 4 में सिमटी

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

साल 2014 में जब से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बंपर जीत हासिल की थी, तब से वह राज्य दर राज्य पूरे देश में अपने पैर पसारती जा रही है। साल 2014 में बीजेपी ने पहली बार हरियाणा में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। इसके बाद साल 2016 में पहली बार असम में केसरिया ध्वज लहरा दिया। अब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके कमाल कर दिया है और एक सुनहरा अध्याय लिख दिया है। अभी देश में भगवा झंडा राजस्थान से लेकर बंगाल तक लहरा रहा है।

इतने राज्यों में बीजेपी की सरकार

भाजपा का 16 राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, बिहार और उत्तराखंड) में खुद का मुख्यमंत्री है और वह सीधे शासन करती है। इसके अलावा अब पश्चिम बंगाल में भी उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और इस तरह से देश के 17 राज्यों में सीधे उसकी सरकार होगी।

देश के सिर्फ चार राज्यों में है कांग्रेस

दूसरी तरफ कांग्रेस के गठबंधन ने केरल में अच्छा प्रदर्शन किया है और वहां पर उसका मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। ऐसे में सिर्फ चार राज्य ही ऐसे होंगे, जहां पर कांग्रेस सीधे सरकार बनाएगी और उसका मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस की केरल, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में सरकार मौजूद है. इसके अलावा वह झारखंड और जम्मू कश्मीर में सहयोगी के रूप में मौजूद है।

सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में ममता बनर्जी को 15 हजार वोटों से दी मात

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। अधिकतर सीटों के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी लगभग 200 सीटें जीतती नजर आ रही है।। बीजेपी ने बहुमत का 148 वाला जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं, टीएमसी 100 सीटें भी नहीं जीत पाई है, जबकि ममता बनर्जी ने लगातार 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया था। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव कराए गए। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को संपन्न हुआ। वहीं मतदान संपन्न होने के बाद आज मतों की गणना हो रही है। ममता बनर्जी के लिए सत्ता बचाना बड़ी चुनौती थी और वह इसे पार करने में विफल रही हैं।

ममता बनर्जी को 15 हजार वोटों से मात

टीएमसी की करारी शिकस्त के बाद पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद भी हार गई हैं। उन्हें भवानीपुर सीट से व्यक्तिगत तौर पर हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की चर्चित सीट भवानीपुर से बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15 हजार 105 के वोटों के अंतर से मात दे दी। यह रिजल्ट बंगाल की सियासत में एक बड़ा मैसेज माना जा रहा है।

ममता का आरोप- बीजेपी ने 100 सीटें लूट लीं

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली हैं। उन्होंने कहा कि अंदर मुझे मारा है, धक्का दिया है। ममता ने कहा कि दोपहर 3 बजे से वे हमें पीट रहे हैं। मुझे मारा गया। सीसीटीवी बंद कर दिया गया था। हमारे किसी भी एजेंट को अंदर (काउंटिंग सेंटर) जाने की इजाजत नहीं थी। डीओ ने मुझे भरोसा दिलाया कि हमारे एजेंट को जाने दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद वह कहीं भी नहीं मिले। मैंने हर जगह शिकायत की। उन्होंने फिर वापसी करने का दम भी भरा।

बंगाल चुनाव में टीएमसी से कहां हुई चूक

माना जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता विरोधी लहर, कानून-व्यवस्था, बीजेपी की आक्रामक रणनीति और लोकल मुद्दों ने चुनाव का समीकरण टीएमसी के लिए बदल गया। साथ ही, संगठन लेवल पर बीजेपी की मजबूती और बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान का प्रभाव भी देखने को मिला।

हिंसा मुक्त होगा बंगाल: पीएम मोदी

बंगाल और असम में बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से देश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जीत का श्रेय बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन को स्वागत-माला भी पहनाई। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वर्षों की तपस्या आज सफल हुई है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने पूरे देश, विशेषकर बंगाल, को लेकर पांच बड़े संदेश भी दिए।

बीजेपी मुख्यालय से मोदी के 5 संदेश

1. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा की जो प्रवृत्तियां फैली हुई हैं, उन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है। हिंसा के इस अनगिनत चक्र को खत्म किया जाना चाहिए. मैं सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि इस पर रोक लगाने के लिए आगे आएं और विकास में भागीदारी निभाएं।
2. मोदी ने अपने भाषण में कहा कि यह बदला का वक्त नहीं है, बदलाव का वक्त है। हिंसा की कोई जगह अब बंगाल में नहीं है। जो लोग ऐसा करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल में अब सिर्फ सेवा के लिए काम हो। भय नहीं, वहां पर अब सिर्फ भविष्य की बात हो।
3. प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान गंगा और ब्रह्म पुत्र नदियों के जरिए हिंदुत्व को भी टच करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगोत्री से गंगासागर तक अब बीजेपी की सरकार है। इसकी अनुभूति मुझे हो रही है। उन्होंने असम जीत को ब्रह्म पुत्र से जोड़ा। दोनों नदियों का हिंदू धर्म में काफी महत्व है।
4. महिलाओं को लेकर भी पीएम मोदी ने अपने भाषण में बड़ा संदेश दिया। मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने महिला आरक्षण रोकने की कोशिश की थी, उन्हें वहां की माताओं और बहनों ने सबक सिखा दिया है। डीएमके, टीएमसी और कांग्रेस को महिलाओं की वजह से चुनाव में करारी हार मिली है।
5. अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने आगे की रूपरेखा भी स्पष्ट कर दी। अब उनकी नजर यूपी पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह डीएमके, टीएमसी और कांग्रेस को मात मिली है, उसी तरह आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को भी माताएं-बहनें सबक सिखाएंगी। समाजवादी पार्टी ने भी आरक्षण में बाधा डालने का प्रयास किया था।

कांग्रेस पर मोदी सबसे ज्यादा हमलावर

अपने भाषण में पीएम मोदी कांग्रेस पर सबसे ज्यादा हमला करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जंगल से नक्सली भगाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का सेंटर बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस को मौका मिला, तो उसने काम नहीं किए। कांग्रेस भले केरल में जीत गई हो, लेकिन यह जीत उसकी नहीं है। पीएम ने कहा कि लोग केरल की कम्युनिष्ट पार्टियों से नाराज थी, जिसके कारण कांग्रेस को जीत मिली है।

बंगाल में बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री?

पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करती नजर आ रही है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जीत के बाद बीजेपी बंगाल की कमान किसके हाथों में देगी और यहां का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को सबसे आगे रखा था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी किसी महिला को मुख्यमंत्री बना सकती है। फिलहाल पांच नाम रेस में हैं।

शुभेंदु अधिकारी

शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद के टॉप दावेदारों में से एक हैं। एक समय में ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी के पास जमीनी पकड़ और मजबूत सांगठनिक नेटवर्क है। 2021 में उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर 'जायंट किलर' का तमगा हासिल किया था। हालांकि, नारदा स्टिंग मामले में उनका नाम शामिल रहा, जो मुख्यमंत्री बनने की राह में उनके लिए रुकावट बन सकता है।

दिलीप घोष

2021 में बीजेपी को मुख्य विपक्षी दल बनाने का श्रेय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को ही दिया जाता है। भले ही वे अब अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन बंगाल की राजनीति में उनका प्रभाव आज भी कायम है। ऐसे में बंगाल सीएम की रेस में वो एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं।

समीक भट्टाचार्य

बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य को पार्टी में सबको साथ लेकर चलने वाले नेता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में बीजेपी उन्हें भी बंगाल की कमान सौंप सकती है।

अग्निमित्रा पॉल

पेशे से फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल बीजेपी की एक बेबाक नेताओं में से एक हैं। उन्होंने इस चुनाव में अपनी आसनसोल दक्षिण सीट बरकरार रखी है। अगर बीजेपी राज्य में महिला सीएम चुनती है तो अग्निमित्रा उनकी पसंद हो सकती हैं।

रूपा गांगुली

पूर्व राज्यसभा सांसद और सोनारपुर दक्षिण से विधायक रूपा गांगुली ने महिला मोर्चा की अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जमीनी स्तर पर भी काम किया है। उनकी पॉपुलैरिटी देखते हुए बीजेपी उन्हें बंगाल का मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर सकती है। निशिथ प्रामाणिक का नाम भी सीएम पद की रेस में सामने आ रहा है।

असम में तीसरी बार सत्ता में बीजेपी

• कांग्रेस 19 सीटों में सिमटी

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने राज्य की राजनीति की तस्वीर लगभग साफ कर दी है। 126 सीटों पर हुई मतगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) स्पष्ट बढ़त बनाए हुए है और लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की ओर बढ़ता दिख रहा है। 9 अप्रैल को सभी 126 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ था, जिसमें राज्य में लगभग 85.5% मतदान दर्ज किया गया। राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 सीटों का है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है। भाजपा अब तक 79 सीटें जीत चुकी और तीन पर बढ़त बनाए हुए है। उसके सहयोगी - असम गण परिषद छह सीटें जीत चुकी और चार पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं, बोडो लैंड पीपुल्स फ्रंट नौ सीटें जीती है और एक पर आगे चल रही है। इस बार के चुनाव में विपक्षी कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनावों से भी खराब रहा। सीटों के लिहाज से दूसरे स्थान पर रही। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक कांग्रेस 12 सीटों में जीत दर्ज की और 8 सीटों में बढ़त बनाए हुए है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) केवल दो सीटें जीती। पिछले चुनाव में एआईयूडीएफ 15 सीटें जीती थी। अखिल गोगोई की रायजोर दल ने दो सीटें जीती। तृणमूल कांग्रेस एक सीट जीती। कांग्रेस के नेतृत्व में छह दलों के विपक्षी गठबंधन ने भाजपा विरोधी वोटों को एकजुट करने में नाकाम रही। जहां भाजपा पांच वर्षों तक चुनावी तैयारी में जुटी रही, वहीं कांग्रेस कमजोर स्थिति में मैदान में उतरी, दल-बदल के कारण संगठन कमजोर हुआ और रणनीतिक रूप से भी वह सीमित रही। गठबंधन भी मतदान से कुछ सप्ताह पहले ही अंतिम रूप ले पाया। पिछले विधानसभा में भाजपा ने 64 सीटें जीती थी, जबकि उसके सहयोगियों में एजीपी 9, यूपीपीएल 7 और बीपीएफ 3 सीटें जीती थीं. विपक्ष में कांग्रेस 26, एआईयूडीएफ 15, माकपा 1 और एक निर्दलीय चुनाव जीते थे।

कांग्रेस का प्रमुख चेहरा रहे गौरव गोगोई हार गए

असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख गौरव गोगोई जोरहाट सीट से भाजपा प्रत्याशी से भारी मतों के अंतर से हार गए। गोगोई 23,182 वोटों से भाजपा के हितेंद्र नाथ गोस्वामी से हार गए। गोस्वामी को 69,439 मत मिले, जबकि गोगोई को 47,257 वोट मिले। गोस्वामी दो बार विधायक रह चुके हैं और उन्होंने 2016 और 2021 में यह सीट जीती थी।

सुनेत्रा पवार की ऐतिहासिक जीत

• 2.18 लाख से अधिक वोटों से जीतीं

हिंदमाता नेटवर्क @ बारामती

महाराष्ट्र के बारामती विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) की उम्मीदवार और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन में सुनेत्रा पवार ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें 2019 में उनके पति अजित पवार द्वारा बनाया गया जीत का अंतर भी शामिल है। सोमवार को मतगणना के 24वें चरण के अंत में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सुनेत्रा पवार ने 218,930 वोटों के रिकॉर्ड तोड़ अंतर से जीत हासिल की है। इस जीत को अब भारत के इतिहास में किसी भी विधायक उम्मीदवार की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है। चुनाव में सुनेत्रा पवार के पीछे सत्ता का पूर्ण एकीकरण देखने को मिला। उनके बेटों जय पवार और पार्थ पवार की अपीलों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के समर्थन से वोटों की एक विशाल लहर उत्पन्न हुई।

सुनील कुमार शर्मा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा

एक भी प्रतिद्वंद्वी 1,000 वोटों का आंकड़ा पार नहीं कर सका। सुनेत्रा पवार सहित कुल 23 उम्मीदवार थे। करुणा मुंडे को 125 वोट मिले, जबकि अभिजीत बिचुकले को 121 वोट मिले। इस परिणाम के साथ सुनेत्रा पवार ने आधिकारिक तौर पर साहिबाबाद (उत्तर प्रदेश) के सुनील कुमार शर्मा द्वारा बनाए गए पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 2022 में 2,14,835 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी।

राहुरी उपचुनाव में बीजेपी के अक्षय कर्डिले की बड़ी जीत

हिंदमाता नेटवर्क @ अहिल्यानगर

बीजेपी के उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव कर्डिले ने सोमवार को राहुरी विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की। सोमवार को घोषित नतीजों से पुष्टि हुई कि कर्डिले ने अपने पिता दिवंगत शिवाजी कर्डिले की सीट को सफलतापूर्वक बरकरार रखा है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्षय कर्डिले ने मतगणना के शुरूआती दौर से ही चुनाव में बढ़त बनाए रखी। उन्हें 1,40,093 वोट मिले, जबकि उनके सबसे नजदीकी प्रतिद्वंद्वी शरद पवार की एनसीपी के उम्मीदवार गोविंद मोकाटे को 27,506 वोट मिले। 1.12 लाख से अधिक वोटों का यह भारी अंतर क्षेत्र में बीजेपी की मजबूत पकड़ को दिखाता है, जो उनके पिता शिवाजी कर्डिले द्वारा 2024 के आम चुनाव में हासिल 34,487 वोटों की जीत से कहीं ज्यादा है। राहुरी उपचुनाव अक्टूबर 2025 में वरिष्ठ बीजेपी नेता शिवाजी भानुदास कर्डिले के अचानक निधन के कारण कराना पड़ा।

केरलम में कांग्रेस ने खत्म किया वनवास

• 63 सीटों के साथ बनी सबसे बड़ी पार्टी

केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता में ऐतिहासिक वापसी की है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, केरलम में कांग्रेस ने 10 साल का वनवास खत्म कर लिया है। केरलम में कांग्रेस ने 140 सीटों में से 63 सीटें जीती है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने 26 सीटों पर जीत दर्ज की है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने केरलम चुनाव में 22 सीटें हासिल की है। इसके साथ ही एक बार फिर केरलम में कांग्रेस ने वापसी कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री पिनारई विजयन अपनी सीट बचाने में सफल हुए हैं। पिनारई विजयन ने अपने गृह क्षेत्र धर्मदम से 19 हजार से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है।

प्रचंड जीत के बाद बहुमत से दूर विजय के सामने 4 विकल्प

थामेंगे कांग्रेस का हाथ या लेंगे बीजेपी का साथ?

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

अभिनेता थालापति विजय (52) ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी टीवीके (तमिलगा वेट्री कजगम) के साथ तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। तमिलनाडु में फिल्मी सितारों को नेता चुनने का लंबा इतिहास रहा है। इसी क्रम में अभिनेता से नेता बने थलपति विजय ने द्रविड़ पार्टियों के दबदबे के बीच बड़ा बदलाव किया है। अपने पहले ही चुनाव में वो सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। उनकी पार्टी टीवीके इस समय 107 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जिसमें 77 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। लेकिन बहुत के आकंड़े (118 सीटें) से अभी दूर है। ऐसे में तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए विजय को सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। उनके पास विकल्पों की भरमार है।

पहला विकल्प: विजय एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करने का विकल्प चुन सकते हैं। एआईएडीएमके ने पहले भी टीवीके को चुनाव से पहले गठबंधन के लिए मनाने की कोशिश की थी। हालांकि, टीवीके की मांग के कारण बातचीत टूट गई थी कि उसे राज्य की 234 सीटों में से आधे से ज्यादा सीटें मिलें और विजय को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। एआईएडीएमके अपनी किस्मत चमकाने के लिए टीवीके से हाथ मिलाने को तैयार हो सकती है।

दूसरा विकल्प: विजय ने बीजेपी को अपनी वैचारिक दुश्मन बताया था। इसलिए यदि टीवीके गठबंधन करने के लिए एआईएडीएमके को बीजेपी का साथ छोड़ने की मांग कर सकती हैं। हालांकि यह एक बहुत बड़ी मांग होगी, क्योंकि बीजेपी ने ही बिखरी हुई एआईएडीएमके पार्टियों को एक साथ लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। बीजेपी के साथ जाने में विजय की हिचकिचाहट की एक बड़ी वजह दूसरी भी है। पिछले साल करूर में हुई भगदड़ की घटना के बाद में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद बीजेपी ने विजय पर जोरदार हमले किए थे।

तीसरा विकल्प: यदि विजय डीएमके और एआईएडीएमके के साथ गठबंधन नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में छोटे दलों जैसे पीएमके, डीएमडीके, वीसीके और एएमएमके के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। इससे उन्हें स्वतंत्र पहचान और नियंत्रण मिलेगा। ताजा रुझानों में देखें तो पीएमके के पास 5 सीट, डीएमडीके, वीसीके और एमएमएमके जैसे दलों के पास 2-2 सीटे हैं। इनको लेकर विजय सरकार बना सकते हैं।

चौथा विकल्प: विजय कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस पहले ही समर्थन की बात कह चुकी है, जैसा उसने पिछली डीएमके सरकार में भी किया था।

पुडुचेरी में बीजेपी का जलवा बरकरार

पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव हुआ है, जहां मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की अगुवाई वाली एआईएनआरसी चौथी बार सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है। यहां मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है और नतीजे यह तय करेंगे कि मौजूदा सरकार अपनी पकड़ बनाए रखती है या बदलाव होता है।

भाजपा ने ममता दीदी को पराजय की झालमुड़ी खिलाई : एकनाथ शिंदे

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया है। रुझानों में भाजपा को मिले भारी बहुमत पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को नकारते हुए विकास, स्थिरता और शांति के पक्ष में मतदान किया है। शिंदे ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का शताब्दी वर्ष है। ऐसे में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि (पश्चिम बंगाल) में भाजपा की यह जीत सर्वार्थ में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है।

अमित शाह की रणनीति और कार्यकर्ताओं का संघर्ष

एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों की अथक मेहनत से शाह ने ममता बनर्जी के अभेद्य माने जाने वाले गढ़ को ध्वस्त कर दिया है, जिससे यह एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि वे राजनीति के असली चाणक्य हैं। शिंदे ने उन भाजपा कार्यकताओं को भी बधाई दी, जिन्होंने दमनकारी राजनीति के बावजूद जमीन पर डटकर संघर्ष किया।

उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

सरकारी मशीनरी का 'सायरन' खामोश

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) ने सोमवार को महाराष्ट्र की कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने देशभर में मोबाइल फोन पर इमरजेंसी सायरन टेस्ट करके लोगों को आपदा की चेतावनी देने की कोशिश की, वहीं महाराष्ट्र में जब महिलाओं और छोटी बच्चियों के साथ रोजाना बलात्कार और अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, तो सरकारी मशीनरी का 'सायरन' खामोश है। दरअसल, शिवसेना गुट के मुखपत्र 'सामना' में सोमवार को छपे एक संपादकीय में पुणे जिले के भोर तहसील के नसरापुर में चार साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या की घटना का जिक्र किया गया है। इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में भारी गुस्सा फैल गया। गुस्साए लोग बच्ची का शव सड़क पर लेकर आए और आरोपी को तुरंत उनके हवाले करने की मांग करने लगे ताकि वे खुद न्याय कर सकें, लेकिन इसके बजाय पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। लेख में कहा गया है कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने 'मिसिंग लिंक' टनल प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान लगे ट्रैफिक जाम के लिए जनता से माफी मांगी। नसरापुर, चाकन और नागपुर में छोटी बच्चियों के साथ हुए अमानवीय यौन अत्याचार गृह विभाग की विफलता को दर्शाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को राज्य की सभी छोटी बच्चियों और उनकी माताओं से माफी मांगनी चाहिए।

अपराधियों को अब कानून का कोई डर नहीं रहा

संपादकीय में कहा गया है कि भोर तालुका के नसरापुर गांव में, चार साल की एक बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुणे में अत्याचार और हत्या की घटनाएं चिंताजनक रूप से तेजी से बढ़ रही हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री के अपने शहर नागपुर में भी अत्याचार का शिकार हुई महिलाओं की दिल दहला देने वाली चीखें सुनी जा सकती हैं। सांगली में भी इसी तरह के अत्याचार के मामले सामने आए हैं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों को लेकर सरकार निष्क्रिय बनी हुई है और अपराधियों को अब कानून का कोई डर नहीं रहा।

गृहमंत्री के तौर पर पूरी तरह विफल साबित हुए हैं फडणवीस

आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री फडणवीस राज्य के गृह मंत्री के तौर पर पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। वह राज्य की कानून-व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय दूसरे राज्यों में राजनीतिक प्रचार में व्यस्त रहे। इसमें पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु के दौरों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि महाराष्ट्र की छवि चमकाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट है। राज्य के भीतर भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ रहे हैं और खासकर महिलाओं की सुरक्षा बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है। लेख में भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा गया है कि जब पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में भाजपा ने जोरदार विरोध किया था, तब महाराष्ट्र में हो रही घटनाओं पर वे राजनीति न करने की सलाह दे रहे हैं यानी जहां विपक्ष शासित राज्य होता है, वहां विरोध तेज होता है, लेकिन अपने राज्य में ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साध ली जाती है।

जनता का गुस्सा बढ़ रहा है

संपादकीय में यह भी सवाल उठाया गया है कि सरकार बार-बार फास्ट ट्रैक कोर्ट और फांसी की सजा की बात करती है, लेकिन वास्तव में कितने दोषियों को सजा मिली है। जनता का गुस्सा बढ़ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि सिर्फ बयानबाजी से क्या बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? लेख में सरकार की 'लड़की बहन योजना' पर भी तंज कसा गया है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की सहायता दी जाती है। सवाल उठाया गया है कि क्या सिर्फ 1,500 रुपए देने से सरकार को उन महिलाओं की बेटियों की सुरक्षा की अनदेखी करने का लाइसेंस मिल जाता है?"

विकास परियोजनाएं: गडकरी ने महाराष्ट्र में प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की

हाई-स्पीड, हाई-डेंसिटी और एनएच कॉरिडोर पर चर्चा

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य परियोजनाओं की प्रगति को लेकर खासा गंभीर हैं। इस क्रम में उन्होंने सोमवार को महाराष्ट्र में प्रस्तावित हाई-स्पीड कॉरिडोर, हाई-डेंसिटी कॉरिडोर और अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर की समीक्षा की। गडकरी ने यहां हुई समीक्षा बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण राजमार्ग विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। इसमें नागपुर-भंडारा खंड का छह लेन का निर्माण, तलोदा-बुरहानपुर खंड का चार लेन का निर्माण, दुर्ग-गडचिरोली-मंचरियाल कॉरिडोर, गडचिरोली-कांकेर (रायपुर-विशाखापत्तनम) कॉरिडोर, ग्वालियर-नागपुर कॉरिडोर, नागपुर-हैदराबाद कॉरिडोर, भंडारा-रायपुर खंड का छह लेन का निर्माण, लखनादोन-दुर्ग-रायपुर कॉरिडोर, नागपुर-अमरावती खंड का छह लेन का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही एनएच-44 पर मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र सीमा-नागपुर बाईपास-बोरखेड़ी खंड और पुणे-सतारा खंड का छह लेन के निर्माण को लेकर भी चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने समीक्षा बैठक में महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 527 किमी की कुल लंबाई को कवर करने वाली नौ राज्य निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण (बीओटी) परियोजनाओं पर भी चर्चा शामिल थी। इन परियोजनाओं में शिरूर-अहिल्यानगर (4-लेन), अहिल्यानगर-वडाला (4-लेन), वडाला-छत्रपति संभाजी नगर (4-लेन), छत्रपति संभाजी नगर-जालना (4-लेन), जालना-वातूर (4-लेन), नांदेड़-नरसी-डेगलुर (4-लेन और 2-लेन), जाम-वरोरा (4-लेन), वरोरा-चंद्रपुर-बामनी (4-लेन) और मलकापुर-चिखली (2-लेन) गलियारे शामिल हैं। इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में सड़क संपर्क को मजबूत करने और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन में तेजी लाना था।

खारीगांव टोल प्लाजा फिर शुरू करने की तैयारी

एनसीपी का विरोध तेज

हिंदमाता संवाददाता @ ठाणे

माजीवाड़ा-वडपे प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सरकार ने एक बार फिर खारीगांव टोल प्लाजा पर टोल वसूली की तैयारी की है। इस टोल प्लाजा पर लगभग 9 साल पहले टोल वसूली बंद कर दी गयी थी। टोल वसूली की सुगबुगाहट के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने टोल वसूली के खिलाफ आक्रामक भूमिका अख्तियार की है। राकां (एसपी) के ठाणे शहर अध्यक्ष मनोज प्रधान ने ठाणेवासियों को टोल से छूट की मांग करते हुए टोल प्लाजा बंद करने की धमकी दी है। मुंबई-नाशिक हाईवे पर माजीवाड़ा से वडपे प्रोजेक्ट का काम 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है और इस लेन का निर्माण अगले कुछ महीनों में पूरा होने की संभावना है।

खारीगांव टोल प्लाजा पर 9 वर्ष पहले बंद हुई थी वसूली

इससे मुंबई-नाशिक हाईवे और समृद्धि महामार्ग के माध्यम से मुंबई की ओर यात्रा तेज व बेहतर होगी, लेकिन ड्राइवरों को टोल का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, खारीगांव में पुराने टोल प्लाजा क्षेत्र में एक नया टोल प्लाजा बनाने का काम शुरू हो गया है। राकां (एसपी) के ठाणे शहर जिला अध्यक्ष मनोज प्रधान ने कहा कि खारीगांव टोल प्लाजा वर्ष 1998 में शुरू किया गया था।

कई बार हुए विरोध प्रदर्शन

टोल वसूली के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन हुए थे। वर्ष 2017 में यह टोल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। इस वजह से ठाणे से भिवंडी, कल्याण और कल्याण, भिवंडी, नाशिक, उरण जेएनपीए जाने वाले हजारों हल्के, भारी और हैवी गाड़ी चलाने वालों को टोल से छूट मिल गई थी। टोल वसूली बंद हुए अभी सिर्फ 9 साल हुए है, माजीवाडा-वडपे प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद एकबार फिर टोल वसूली शुरू की जाएगी। जिसका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करेगी, उन्होंने कहा कि गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स तो लिया ही जाता है, लेकिन पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे नागरिकों पर फिर से टोल लगाकर शोषण करने की कोशिश की जा रही है।

एम्बुलेंस-शव वाहन शुल्क पर विवाद

पारदर्शिता की मांग तेज

हिंदमाता संवाददाता @ मीरा-भायंदर

मीरा-भायंदर मनपा क्षेत्र में मरीजों और उनके परिजनों से एम्बुलेंस तथा शव वाहन सेवाओं के नाम पर कथित आर्थिक शोषण का मुद्दा अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। पारदर्शिता की कमी और मनमाने शुल्क वसूले जाने की शिकायतों के बीच स्थानीय नगरसेविका फ्रीडा डिमेलो ने इस पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। डिमेलो ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को ज्ञापन सौंपकर सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस और शव वाहन सेवाओं की स्पष्ट शुल्क सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने की मांग की है। उनका कहना है कि दरों की जानकारी के अभाव में आम नागरिक अक्सर निजी सेवाओं के महंगे और मनमाने शुल्क देने को मजबूर हो जाते हैं। मीरा-भाईंदर मनपा क्षेत्र में भले ही मुफ्त एम्बुलेंस और शव वाहन सेवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन सीमित संख्या और खराब रखरखाव के कारण ये सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं। कई वाहन जर्जर हालत में हैं, जिससे मरीजों को मजबूरी में निजी सेवाओं का सहारा लेना पड़ता है। स्थिति यह है कि शहर के पंडित भीमसेन जोशी सरकारी अस्पताल जैसे प्रमुख अस्पतालों में भी पर्याप्त एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हैं।

संचालकों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई

फ्रीडा डिमेलो, स्थानीय नगरसेविका, शिवसेना ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। मौजूदा परिस्थितियों में यह स्पष्ट होता है कि अस्पतालों के बाहर अनिवार्य रूप से शुल्क सूची प्रदर्शित करना समय की जरूरत बन गया है, ताकि आम नागरिकों को आर्थिक शोषण से राहत मिल सके।

शुरू करें हेल्पलाइन

कुछ मामलों में तय दरों पर सेवाए मिलती है, लेकिन अधिकतर शिकायते मनमाने शुल्क वसूले जाने की सामने आ रही हैं। डिमेलो के अनुसार अस्पतालों के बाहर शुल्क सूची प्रदर्शित करने से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोग सही विकल्प चुन सकेंगे। साथ ही उन्होंने इन सेवाओं की निगरानी के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र और शीघ्र शिकायत निवारण हेल्पलाइन शुरू करने की भी मांग की है।

ठाणे- अमने एलिवेटेड रोड को हरी झंडी

समृद्धि महामार्ग पर जाम से मिलेगी राहत

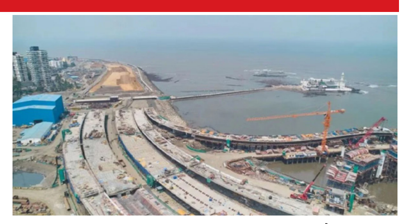

हिंदमाता संवाददाता @ ठाणे

मुंबई एवं ठाणे से नागपुर की यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। समृद्धि महामार्ग से यात्रा को अब और अधिक आसान बनाने के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) ने एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। ठाणे (साकेत) और अमने के बीच एक एलिवेटेड रोड को हरी झंडी मिल गई है। एमएमआरडीए ने इस प्रोजेक्ट के लिए वन विभाग से मंजूरी के लिए एक प्रपोजल पेश किया है। समृद्धि हाईवे की वजह से मुंबई और नागपुर के बीच सफ़र तेज हो गया है। लेकिन हाईवे पर एंट्री लेते या बाहर निकलते समय यात्रियों को ट्रैफ़िक जाम से गुजरना पड़ता है। एलिवेटेड रोड बनने से बिना किसी रुकावट के यात्रा हो सकेगी। फिलहाल ठाणे में वडपे इंटरचेंज के पास ट्रैफ़िक जाम की वजह से सफ़र में दिक्कत होती है। लेकिन इस एलिवेटेड रोड की वजह से यह सफ़र जाम से मुक्त हो जाएगा।

राज्य का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट

हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग राज्य का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस महामार्ग की कुल लंबाई 701 किमी होने की वजह से, मुंबई से नागपुर यात्रा का समय 17 घंटे से घटकर सिर्फ 8 घंटे रह गय है। जून 2025 में इगतपुरी से अमने तक के आखिरी 76 किमी लंबे हिस्से के उद्घाटन के बाद यह हाईवे पूरी तरह चालू हो गया है। यह महामार्ग राज्य के 10 जिलों से होकर गुजरता है। नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, अहमदनगर, नाशिक और ठाणे। जबकि फीडर नेटवर्क के जरिए यह हाईवे 14 जिलों को जोड़ता है।

2025 में सबमिट हुई रिपोर्ट

अभी, इस मार्ग पर अंजुर और भिवंडी इलाकों में बड़े गोदाम होने की वजह से, अमने से ठाणे तक के हिस्से पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। मुंबई-नाशिक हाईवे पर हर दिन बहुत सारी गाड़ियां चलती है। 24/7 ट्रैफिक पुलिस मैनेजमेंट के बावजूद हालात में ज्यादा बदलाव नहीं आया है, जिसकी वजह से एमएमआरडीए ने इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन निकाला है।

भिवंडी में निलंबित 9 कर्मचारियों की बहाली

यूनियन ने महापौर का जताया आभार

हिंदमाता नेटवर्क @ भिवंडी

भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका (मनपा) के 9 कर्मचारियों को निलंबित किए जाने के मामले में बड़ा मोड़ आया है। प्रशासन के इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए भारतीय कामगार कर्मचारी यूनियन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद सभी कर्मचारियों को दोबारा सेवा में बहाल कर लिया गया। यूनियन के अध्यक्ष भानुदास भसाळे, सचिव श्रीपत तांबे और प्रमुख सलाहकार नगरसेवक प्रशांत लाड सहित शेखर जाधव, रविंद्र वारघडे, चंद्रकांत भोईर व अन्य पदाधिकारियों ने इस मुद्दे को लेकर आयुक्त और महापौर नारायण चौधरी से मुलाकात की थी। उन्होंने मनपा प्रशासन की कार्रवाई को कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए महापौर नारायण चौधरी ने पहल करते हुए आयुक्त अनमोल सागर को लिखित पत्र भेजा और निलंबित कर्मचारियों को तुरंत काम पर वापस लेने की मांग की। महापौर के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए सभी 9 कर्मचारियों को पुनः सेवा में शामिल कर लिया। कर्मचारियों की बहाली के बाद भारतीय कामगार कर्मचारी यूनियन और संबंधित कर्मचारियों ने महापौर नारायण चौधरी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर धन्यवाद दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम से कर्मचारियों में राहत का माहौल है, वहीं यूनियन ने इसे न्याय की जीत बताया है।

एसी लोकल पर यात्री गर्म: पश्चिम रेलवे की विरार-चर्चगेट लोकल ट्रेन के यात्रियों ने सोमवार सुबह 8:28 बजे विरार रेलवे स्टेशन को रोककर जोरदार विरोध किया। कई सालों से आम लोगों के लिए चल रही इस सामान्य लोकल ट्रेन को अचानक एसी ट्रेन में बदल दिया गया, जिससे गुस्साए यात्रियों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कुछ देर के लिए सर्विस रोक दी। इससे स्टेशन एरिया में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया।

हिंदमाता एंकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को करीब 6995 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है

नमक उत्पादन भूमि का निजी मालिकाना हक बरकरार, हाई कोर्ट के फैसले से बड़ा झटका केंद्र को

हिंदमाता नेटवर्क @ मीरा-भायंदर

मीरा-भाईंदर स्थित 220 एकड़ नमक उत्पादन भूमि को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यह भूमि निजी स्वामित्व में ही रहेगी और केंद्र का दावा कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अनखद की पीठ ने 30 अप्रैल को दिए गए अपने निर्णय में कहा कि वर्ष 1870 के समझौते के तहत यह भूमि रामचंद्र लक्ष्मण और उनके उत्तराधिकारियों को 999 वर्षों के पट्टे पर दी गई थी, जिसमें केवल उपयोग का अधिकार ही नहीं बल्कि पूर्ण स्वामित्व भी शामिल था।

नमक उत्पादन के लिए उपयोग में लायी जा रही थी भूमि

केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया था कि चूंकि इस भूमि का उपयोग लंबे समय से नमक उत्पादन के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसे सरकारी संपत्ति माना जाना चाहिए। साथ ही 1935 के अधिनियम के आधार पर स्वामित्व का दावा भी पेश किया गया था। हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि विवादित भूमि किसी भी सरकारी सूची में शामिल नहीं थी और केवल नमक उत्पादन के लिए लाइसेंस दिए जाने से स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं होता।

लंबे समय तक कोई दावा नहीं किया गया था

अदालत ने यह भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि केंद्र सरकार ने इस भूमि पर अपना दावा 1983 के बाद प्रस्तुत किया, जबकि उससे पहले लंबे समय तक कोई दावा नहीं किया गया था। इस कारण यह दावा समय सीमा के आधार पर भी स्वीकार्य नहीं माना जा सकता।

उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र गाडलिंग को जमानत दी

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

बंबई उच्च न्यायालय ने 2018 के एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र गाडलिंग को सोमवार को जमानत दे दी। अदालत ने यह राहत उनकी लंबी अवधि की हिरासत और निकट भविष्य में मुकदमे की सुनवाई शुरू होने की संभावना कम होने के आधार पर प्रदान की। न्यायमूर्ति ए। एस। गडकरी की अगुवाई वाली पीठ ने गाडलिंग की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामले के अन्य सभी आरोपी पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं, इसलिए समानता के आधार पर गाडलिंग को भी यह राहत मिलनी चाहिए। इस फैसले के साथ ही आठ साल से अधिक पुराने इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी अब जमानत पर बाहर हैं। गौरतलब है कि इस मामले में 84 वर्षीय पादरी एवं आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी की जुलाई 2021 में हिरासत में रहते हुए मृत्यु हो गई थी। महाराष्ट्र के पुणे में 31 दिसंबर, 2017 को आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में प्रमुख वकीलों, कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों सहित कम से कम 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, इन भाषणों के कारण अगले दिन पुणे शहर के बाहरी इलाके कोरेगांव-भीमा में हिंसा भड़क उठी थी। शुरुआत में मामले की जांच पुणे पुलिस ने की थी, जिसने दावा किया था कि इस सम्मेलन को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था। बाद में इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने अपने हाथ में ले ली। इस मामले के अन्य आरोपियों में वरवर राव, सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबडे, वर्नोन गोंसाल्वेस, अरुण फरेरा, शोमा सेन, गौतम नवलखा, सुधीर धवले, रोना विल्सन, ज्योति जगताओ और महेश राउत शामिल हैं।

बिजनेस वर्ल्ड

भाषा के नाम पर सियासी रोटी सेंकने का काम हो रहा:अबू आसिम आजमी

हिंदमाता संवाददाता @ मुंब्रा

समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के नेता एवं विधायक अबू आसिम आजमी मुंब्रा पार्टी कार्यालय उद्घाटन समारोह में पहुंचे जहां उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा के मराठी मुद्दा सिर्फ एक राजनीति है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बलात्कार और और दूसरे अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है, किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है और इन सब पर पर्दा डालने के लिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कभी हिंदू-मुस्लिम तो कभी मुसलमानों को टारगेट करना तो कभी हिंदी मराठी भाषा को लेकर जनता के बीच मुद्दा छेड़ देना ताकि लोग इसमें उलझे रहें और सरकार की नीतियों पर कोई सवाल ना उठाएं। अबू आसिम ने कहा कि हमारी पार्टी का मुंब्रा में नया अध्यक्ष बना है और संगठन को नए ढंग से व्यवस्थित किया गया है। आजमी ने कहा कि अब हम पूरी ताकत के साथ यहां पर फिर से पार्टी को उभारेंगे। इस मौके पर यहां कई लोगों ने पक्ष प्रवेश भी किया। मुंब्रा अध्यक्ष शब्बीर खान ने उन सबका स्वागत किया।

नवी मुंबई में खुले मैदान में फिर आग लगी; कोई घायल नहीं

हिंदमाता संवाददाता @ ठाणे

नवी मुंबई के उस खुले मैदान में सोमवार को फिर आग लग गई जहां एक दिन पहले भी आग लगी थी। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। भंडार्ली गांव में रविवार दोपहर को मैदान में पड़े कबाड़ में आग लग गई थी। ऐरोली, कोपरखैरणे और नेरुल से अग्निशमन विभागों से दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं जबकि ठाणे महानगरपालिका से भी दमकल की गाड़ियां घटना स्थल पर भेजी गईं जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर कबाड़ जमा होने के कारण सोमवार को आग फिर से भड़क उठी। आग पर काबू पाने के लिए पानी का टैंकर घटनास्थल पर भेजा गया। दमकल अधिकारी ने बताया कि मलबा हटाने में मदद के लिए एक खुदाई मशीन भी बुलाई गई थी। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर घने धुएं के कारण आग बुझाने के प्रयास मुश्किल हो गए थे।

चंद्रपुर किडनी बिक्री मामला: महत्वपूर्ण फैसले में अदालत ने कहा - गिरफ्तारी के बाद अग्रिम जमानत का अधिकार नहीं, चाहे ट्रांजिट बेल मिली हो

हिंदमाता नेटवर्क @ चंद्रपुर

चंद्रपुर जिले की नागभीड़ तहसील निवासी रोशन कुले की किडनी बिक्री से उजागर हुए अंतरराष्ट्रीय रैकेट के मुख्य संदिग्ध आरोपी डॉ. रवींद्रपाल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति रजनीश व्यास की एकलपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यदि किसी आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वह अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं रहता, भले ही उसे पूर्व में ट्रांजिट बेल के रूप में अंतरिम राहत प्रदान की गई हो। चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक गंभीर अपराध में डॉ. रवींद्रपाल सिंह का नाम जांच के दौरान सामने आया। उन पर जबरन वसूली, आपराधिक साजिश और अवैध मानव अंग प्रत्यारोपण से जुड़े आरोप लगाए गए। आरोपी को 30 दिसंबर 2025 को दिल्ली में गिरफ्तार कर रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें ट्रांजिट बेल दी गई और 2 जनवरी 2026 को चंद्रपुर की अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया। हालांकि, आरोपी निर्धारित तिथि पर चंद्रपुर कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसके बजाय अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया। सत्र न्यायालय ने यह आवेदन खारिज कर दिया, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

ताला तोड़कर चोरी करनेवाला गिरफ्तार तीन तोले सोने के गहने सहित लगभग छह लाख का माल बरामद

हिंदमाता नेटवर्क @ठाणे

यहां मुंब्रा में कुछ घंटों के लिए घर बंद करके बाहर गए और घर में चोरी हो गई, लेकिन पुलिस ने भी अपनी सतर्कता से आरोपी को पकड़कर चोरी गए माल को बरामद कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद सोदू इस्लाम खान(29) जो पेशे से टेलर हैं,अपने परिवार सहित सुल्ताना बिल्डिंग अमृतनगर में रहते हैं। घर बंद करके परिवार के साथ तिलकनगर टर्मिनल कुर्ला में अपनी मां और पिता को लाने गऐ थे। और जब कुछ देर बाद लौटे तो घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला और अंदर अलमारी से नकदी और जेवरात गायब थे। तुरंत पुलिस को खबर कि शिकायत पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने अपराध की प्रकृति, अपराध की गंभीरता एवं अज्ञात आरोपियों की पहचान करने एवं प्रकरण सामग्री जब्त करने के लिए घटना स्थल के आसपास लगे 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज की जांच की एवं तकनीकी जांच के आधार पर एक संदिग्ध के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तदनुसार गोपनीय मुखबिरों के माध्यम से संदिग्ध की तलाश की गई। संदिग्ध की पहचान अल्ताफ शनवर शेख (उम्र 19) के रूप में हुई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके पास से चोरी का सारा सामान, जिसमें 3 तोला सोना और 1,96,000/- रुपए कैश शामिल थे, जब्त कर लिया गया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शिंदे ने कहा कि गहने और नकदी मिलाकर लगभग 5,81,000 की संपत्ति बरामद की गई है।

बंगाल में वंदे मातरम! बीजेपी की जीत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि

हिंदमाता नेटवर्क @ठाणे

पश्चिम बंगाल के चुनाव में जनता ने राष्ट्रवाद को चुना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को जनादेश दिया । जनता ने अत्याचार , प्रांतवाद , भाषावाद और मुस्लिम तुष्टिकरण को सिरे से नकार दिया है । पश्चिम बंगाल के साथ असम और पुंडुचेरी सहित पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और सुशासन को स्वीकार किया है ।

आचार्य पवन त्रिपाठी , कोषाध्यक्ष , श्री सिद्धिविनायक मंदिर , महामंत्री , मुंबई भाजपा

धोखाधड़ी के मामले में 'स्वयंभू बाबा' खरात को हिरासत में लिया गया

हिंदमाता नेटवर्क @ नाशिक

शिरडी पुलिस ने सोमवार को धोखाधड़ी के एक मामले की जांच के सिलसिले में 'स्वयंभू बाबा' अशोक खरात को हिरासत में ले लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मामला अहिल्यानगर जिले के शिरडी में स्थित पिंपलवाड़ी के रहने वाले किसान रावसाहेब नानासाहेब गोंडकर (55) की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र साहूकारी (विनियमन) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता गोंडकर ने आरोप लगाया है कि अगस्त 2023 से खरात, उसकी पत्नी कल्पना खरात और तीन अन्य लोगों ने मिलकर गोंडकर से पांच करोड़ रुपये की ठगी की। अधिकारी ने बताया, 'शिरडी पुलिस ने खरात को हिरासत में ले लिया है। खरात के खिलाफ इस नौवें मामले में उसे कल अहिल्यानगर में स्थित राहाता अदालत में पेश किया जाएगा।' पुलिस के मुताबिक, खरात को मार्च में कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसके बैंक लेनदेन और जमीन सौदों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच की गई।

आईआईआईटी नागपुर के छात्र ने आत्महत्या की

हिंदमाता नेटवर्क @ नागपुर

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) नागपुर के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के एक छात्र ने सोमवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। बुटीबोरी थाने के एक अधिकारी ने बताया कि कोल्हापुर के रहने वाले श्रेयस चंद्रकांत माने (20) ने तड़के करीब 4:30 बजे परिसर में स्थित अपने छात्रावास की छत से छलांग लगा दी। सहायक निरीक्षक नीलेश चौरे ने कहा, ''वह कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष का छात्र था। आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। हम व्यक्तिगत और शैक्षणिक समेत सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रहे हैं।

हम जश्न नहीं मनाएंगे क्योंकि...

बारामती से सुनेत्रा पवार की जीत पर ऐसा क्यों बोले बेटे जय पवार?

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

महाराष्ट्र की हॉट सीट बारामती विधानसभा उपचुनाव में उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख सुनेत्रा पवार एकतरफा और ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही हैं। 13वें राउंड की गिनती के बाद उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों की निर्णायक बढ़त बना ली है, जबकि उनके 22 प्रतिद्वंद्वी 500 वोटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके हैं। इस प्रचंड जीत पर उनके बेटे जय पवार ने बारामती की जनता का आभार जताया। हालांकि, इस भारी जीत के बावजूद जय पवार ने समर्थकों से एक बेहद भावुक अपील की है।

हम में से कोई ऐसा चुनाव नहीं चाहता था

बेटे जय पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके परिवार और समर्थकों को इस जीत का कोई जश्न नहीं मनाना चाहिए। उन्होंने भरे मन से कहा कि क्योंकि हम में से कोई भी इस तरह का चुनाव नहीं चाहता था। दरअसल, यह उपचुनाव 28 जनवरी को बारामती हवाई पट्टी के पास हुए उस दर्दनाक विमान हादसे के कारण हुआ है, जिसमें उनके पिता और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया था। इसके साथ ही जय ने बताया कि पड़ोस के भोर तहसील में 4 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या की दुखद घटना के चलते भी उन्होंने जीत का जश्न न मनाने का फैसला किया है। सुनेत्रा पवार ने भी कार्यकर्ताओं से विजय जुलूस न निकालने और 'गुलाल' न उड़ाने की अपील करते हुए इस जीत को अपने दिवंगत पति की यादों को समर्पित किया है।

मैं हर गुरुवार जनता के लिए रहूंगा मौजूद

चुनाव प्रचार की पूरी कमान संभालने के सवाल पर जय पवार ने विनम्रता दिखाते हुए कहा कि इस सफलता में मैं अकेला नहीं था। हर शुभचिंतक इस अभियान और मतदान में हमारे साथ खड़ा था, उसी की बदौलत हम यह मुकाम हासिल कर पाए। बारामती की जनता से जुड़ने के लिए जय ने एक बड़ा वादा करते हुए ऐलान किया कि वह अब से हर गुरुवार को निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनने और सुलझाने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

अजित पवार का पुराना पद छिनने पर क्या बोले जय?

महाराष्ट्र ओलंपिक संघ (MOA) के प्रमुख पद पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुरलीधर मोहोल की निर्विरोध नियुक्ति (यह पद पहले अजीत पवार के पास था) पर जय ने अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनसीपी यह अध्यक्ष पद अपने पास बरकरार रखना चाहती थी। जय पवार ने कहा कि मुझे कल खेल जगत से इस संबंध में कई फोन आए थे, लेकिन हमारे लिए आज के उपचुनाव के नतीजे ज्यादा अहम थे, इसलिए हम कल कोई फैसला नहीं ले सके। हम संभव हुआ तो मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

बांद्रा ईस्ट में जारी रहेगी झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई : बॉम्बे हाईकोर्ट

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

मुंबई के बांद्रा ईस्ट स्थित गरीब नगर में सभी अवैध और अनधिकृत ढांचों को हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे को तोड़क कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दे दी है। रेलवे की यह कार्रवाई पहले ही चल रही है। कई लोगों ने इस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को अदालत ने अनसुना कर दिया। अदालत ने कहा कि 10 अगस्त 2021 और 11 अगस्त 2021 को हुए पहले और दूसरे सर्वे में चिन्हित पात्र झुग्गीवासियों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस मामले में दायर याचिकाओं पर अदालत 8 जुलाई 2026 को आगे सुनवाई करेगी।

रेलवे ट्रैक के पास हो रही कार्रवाई

रेलवे द्वारा की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई को अदालत ने जायज ठहराया है और इसे जारी रखने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने साफ किया है कि अगस्त 2021 में हुए सर्वेक्षण (सर्वे) में चिह्नित पात्र झुग्गीवासियों को बेघर न किया जाए और उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। रेलवे ट्रैक के पास के उन अवैध ढांचों को हटाया जा रहा है, जिन्हें अतिक्रमण के रूप में पाया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई 2026 को होनी है।

44 एकड़ में पुनर्विकास की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने बांद्रा के भारत नगर में 44 एकड़ क्षेत्र में पुनर्विकास की मंजूरी दी है, जिससे 7,000 से ज्यादा परिवारों का पुनर्वास होगा। महाराष्ट्र में पहले पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए झुग्गीवासियों की सहमति जरूरी थी, लेकिन अब सरकार इसे हटा लिया है। अब प्रशासन बिना झुग्गीवासियों की अनुमति लिए विकास कार्य शुरू कर सकता है और झुग्गियों को उनकी जगह से हटा सकता है। इससे बांद्रा सहित मुंबई भर में परियोजनाओं की गति तेज हो गई है। पश्चिमी रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस के पास की अवैध बस्तियों को ध्वस्त कर वहां फेंसिंग शुरू कर दी है।

टीसीएस मामले में निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

नासिक की एक अदालत ने कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मामले में टीसीएस कर्मचारी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता का 'सुनियोजित तरीके से' 'ब्रेनवाश' करके उसे मलेशिया भेजने की 'एक सुनियोजित साजिश' थी। अदालत ने कहा कि खान की याचिका में कोई दम नहीं है। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता वास्तव में बहुआयामी और बहुस्तरीय है तथा मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।

■ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (नासिक रोड) के. जी. जोशी का आदेश सोमवार को उपलब्ध हुआ। अदालत ने अपने तर्कों सहित दिए गए आदेश में कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से पता चलता है कि आरोपी की पीड़िता का नाम बदलने के बाद उसे मलेशिया भेजने की योजना थी। अभियोजन पक्ष द्वारा उससे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता पर जोर दिये जाने के बाद अदालत ने खान की याचिका दो मई को खारिज कर दी। प्राथमिकी के अनुसार, खान ने कथित तौर पर महिला कर्मचारियों को इस्लामी परंपराओं के अनुसार कपड़े पहनने और व्यवहार करने की सलाह दी थी। उसने गर्भावस्था का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था। पुलिस ने कहा था कि खान की महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में तलाश जारी है।

■ आदेश में कहा गया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की भूमिका का विशेष रूप से (प्राथमिकी में) उल्लेख किया गया है और उसकी संलिप्तता भी दिखती है। न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि निस्संदेह पीड़िता को किसी भी धर्म का अनुसरण करने और अपनी पसंद का नाम रखने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसके लिए उसका 'ब्रेनवाश' किया जाए और वह भी एक संगठित योजना के तहत। देवलाली पुलिस थाने में दर्ज विशेष मामले में, खान और दो अन्य सह-आरोपी, दानिश शेख और तौसीफ (सभी टीसीएस की नासिक इकाई में पीड़िता के सहकर्मी) पर भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत विवाह का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना, यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने आदि के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। उन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

■ पुलिस के अनुसार, दानिश शेख ने विवाह का झूठा वादा करके पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया, जबकि तौसीफ ने बार-बार उससे छेड़छाड़ की और शेख के साथ उसके कथित संबंध को महिला के परिवार के सामने उजागर करने की धमकी देकर उस पर यौन संबंध बनाने का दबाव डाला। प्राथमिकी के अनुसार, खान ने अपने दोनों सह-आरोपियों के साथ मिलकर पीड़िता को डराकर और उसकी धार्मिक भावनाओं को बार-बार ठेस पहुंचाकर उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। पुलिस की ओर से पेश हुए जिला सरकारी अभियोजक (डीजीपी) ए एस मिश्र ने दलील दी कि पीड़िता को आरोपियों के धार्मिक रीति-रिवाजों और दैनिक धार्मिक दिनचर्या का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था।

■ मिश्र ने कहा कि जांच से पता चलता है कि खान ने पीड़िता को बुर्का और पैगंबर मोहम्मद के जीवन पर किताबें दी थीं। मिश्र ने बताया कि उसने मोबाइल में मुस्लिम सिद्धांतों और धार्मिक गतिविधियों से संबंधित एप्लिकेशन भी इंस्टॉल किए थे। जांच का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पीड़िता का नाम बदलकर हानिया रखा जाना था और उसे मलेशिया भेजा जाना था। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में, यह पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है कि क्या कोई अंतरराष्ट्रीय गिरोह इसमें शामिल है और क्या याचिकाकर्ता (खान) उससे जुड़ी हुई है।

■ पीड़िता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एम जी कुरकुटे और नितिन पंडित ने दलील दी कि आरोपियों ने कंपनी में अपने पद का अनुचित लाभ उठाकर पीड़िता को उनका धर्म मानने के लिए मजबूर किया। उन्होंने (आरोपियों ने) पीड़िता की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उसे मांसाहारी भोजन खाने के लिए मजबूर किया और कार्यालय में उसकी जाति को लेकर उसका अपमान भी किया। खान के अधिवक्ता राहुल कसलीवाल ने दलील दी कि चूंकि पीड़िता और याचिकाकर्ता एक ही कार्यालय में कार्यरत थे, इसलिए वे एक-दूसरे को जानती थीं और प्रतिदिन मिलती थीं।

■ उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता की धार्मिक भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। खान की तीन महीने की गर्भावस्था का हवाला देते हुए, कसलीवाल ने दलील दी कि यदि उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो बच्चे को अपूरणीय क्षति होगी। अदालत ने कहा कि जांच खान की संलिप्तता की ओर इशारा करती है, और प्राथमिकी में उसकी भूमिका स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। उसने कहा कि प्राथमिकी में विशेष रूप से खान और अन्य आरोपियों की भूमिका का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने हिंदू धर्म के देवी-देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक कहानियां सुनाकर पीड़िता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।

■ अदालत ने कहा कि कथित अपराध पीड़िता का सुनियोजित तरीके से ब्रेनवाश करने का एक सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है। न्यायाधीश ने कहा कि अग्रिम जमानत देना, कुछ हद तक, अपराध की जांच के क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा। अदालत ने कहा कि पीड़िता पर अनुचित प्रभाव डालने, धमकी देकर या अन्य तरीके से किसी विशेष धर्म को थोपने या उस पर दबाव डालने के संबंध में विस्तृत जांच आवश्यक है। आदेश में कहा गया है कि कथित अपराध की गंभीरता और व्यापकता, याचिकाकर्ता की भूमिका और स्थापित कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह अग्रिम जमानत का मामला नहीं है।

■ एक विशेष जांच दल (एसआईटी) टीसीएस इकाई में महिला कर्मचारियों के कथित शोषण, जबरन धर्मांतरण के प्रयास, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न के संबंध में दर्ज नौ मामलों की जांच कर रहा है। एसआईटी ने एक महिला ऑपरेशन मैनेजर सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। टीसीएस ने स्पष्ट किया है कि उसने लंबे समय से किसी भी प्रकार के उत्पीड़न और दबाव के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है और नासिक कार्यालय में यौन उत्पीड़न में कथित रूप से शामिल कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बना दिया मराठी

मुंबई में जारी किए गए 87,347 फर्जी जन्म प्रमाणपत्र, बीएमसी करेगी बड़ा ऑडिट

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

मुंबई के नागरिक प्रशासन में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जहां करीब 87,347 फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी किए जाने का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि ये प्रमाणपत्र कथित तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम पर बनाए गए, जिससे सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह खुलासा बीएमसी के हेल्थ डिपार्टमेंट की जांच में हुआ, जिसने पूरे मामले की गंभीरता को उजागर किया।

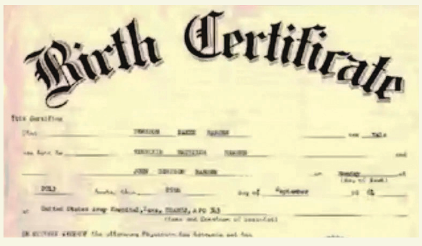

नगर आयुक्त को सौंपी गई रिपोर्ट

आंकड़ों के मुताबिक, 2024 से 2026 के बीच कुल 87,347 फर्जी एंट्री की गई। साल 2024 में 30,507 मामले सामने आए, जो 2025 में बढ़कर 49,705 हो गए, जबकि 2026 में अब तक 7,135 केस दर्ज किए गए हैं। इस पूरे मामले की रिपोर्ट हाल ही में नगर आयुक्त अश्विनी भिडे को सौंपी गई है, बीएमसी ने सभी वाड्र्स में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन का व्यापक ऑडिट कराने का फैसला लिया है।

जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड में हेरफेर

जांच में सामने आया कि मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स (MHOs) ने नियमों का उल्लंघन करते हुए आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने पुराने SAP-CPWM सिस्टम का उपयोग कर जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड में हेरफेर किया। यह सीधे तौर पर Registrar General of India द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है, जिससे सिस्टम में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है।

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

बता दें कि यह मामला उस समय सामने आया है, जब मुंबई में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा था। फरवरी में मेयर बनने के बाद रीतु तावड़े ने अवैध घुसपैठियों और फेरीवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब इस पूरे घोटाले के सामने आने के बाद, मुंबई के नागरिक सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

क्लर्क्स को किया गया सस्पेंड

इसके साथ ही पूरे शहर में सिविक विजिलेंस डिपार्टमेंट को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि घोटाले की पूरी परतें खोली जा सकें। रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, 24 वाड्र्स में MHOs का चरणबद्ध तबादला किया जाएगा, ताकि सिस्टम में पारदर्शिता लाई जा सके। पहले चरण में अंधेरी (K West), दहिसर (R North) और भायखला (E Ward) के अधिकारियों के तबादले की तैयारी है। इससे पहले BMC ने M/East वार्ड में 2 MHOs और 2 क्लर्क्स को सस्पेंड किया था और 237 फर्जी प्रमाणपत्र रद्द किए गए थे। साथ ही कुर्ला (L Ward) और भायखला (E Ward) में भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता किरिट सोमैया ने आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सोमैया ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों के भीतर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई नहीं की, तो वे बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करेंगे।

अहम केस में गवाह थे अब्दुला, दोस्त को 25 लाख पहुंचाए थे

बिरयानी के बाद तरबूज खाने से हुई मौत

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

मुंबई के पायधुनी इलाके में बिरयानी के बाद तरबूज खाने से एक परिवार के सभी चार लोगों की मौत हो गई। इस घर के मुखिया अब्दुला डोकाड़िया एक केस में अहम गवाह थे। पुलिस की जांच में उस केस की जानकारियां भी सामने आई हैं। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक जिस केस में मृतक अब्दुल्ला अहम गवाह थे, उसमें एक पति-पत्नी के बीच का विवाद और वित्तीय लेनदेन शामिल है। केस के बारे में जानकारी इक्कठा करते हुए पुलिस को पता चला कि जिस महिला ने केस दर्ज कराया था वह और एक अन्य व्यक्ति जिसकी पहचान आफताब के रूप में हुई है। वह दोनों एक दूसरे के दूर के परिचित रिश्तेदार थे। अब्दुल्ला भी आफताब को जानता था।

दोस्त को पहुंचाए थे 25 लाख रुपए

पुराने केस में हमीदा नाम की महिला जो अमेरिका में मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी वह और आफताब सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आए हालांकि आफताब की शादी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन पहली पत्नी से तलाक के बाद उसने हमीदा से शादी कर ली। आफताब के पिता एक बिल्डर थे हालांकि उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। इसलिए साल 2019 में आफताब ने हमीदा से 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद मांगी। उस वक्त हमीदा ने उसे 25 लाख रुपए दिए और उन पैसों को लेने के लिए आफताब ने उस वक्त अब्दुल्ला को भेजा था। इसलिए केवल अब्दुल्ला ही इस मामले में मुख्य गवाह था।

2023 में हुई थी शिकायत

साल 2020 में आफताब और हमीदा ने शादी कर ली इसके बाद हमीदा अमेरिका से भारत आ गई उस वक्त हमीदा ने आफताब को लगभग 6.30 लाख से ज्यादा की रकम दी... लेकिन आगे चलकर दोनों के बीच विवाद काफी ज्यादा बढ़ने लगे। आफताब पर यह भी आरोप है, कि वह अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाकर हमीदा के साथ दुर्व्यवहार करता था। साल 2023 में हमीदा ने इस मामले में आफताब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

केस से जुड़े लोगों के बयान दर्ज कर रही पुलिस

इस मामले में आफताब के खिलाफ BNS के तहत केस दर्ज किया गया था और उस पर धारा 377, 420, 498-अ, 504 और 506 के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले में अनैसर्गिक कृत्य, धोखाधड़ी, विवाहित महिला पर क्रूरता, जानबूझकर अपमान कर झगड़ा भड़काना और आपराधिक धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मृतक अब्दुल्ला इस केस में एक अहम गवाह थे। पुलिस इस केस से जुड़े हुए लोगों के भी बयान दर्ज कर रही है, हालांकि अभी तक की जांच में पुलिस को दोनों केस के लिंक होने की कोई जानकारी नहीं मिली है।

यौन उत्पीड़न शिकायत

अदालत ने कूपर अस्पताल के डीन के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाया

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

मुंबई उच्च न्यायालय ने निगम द्वारा संचालित कूपर अस्पताल के डीन सुधीर मेधेकर के खिलाफ एक समिति द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया है। समिति ने उक्त टिप्पणी मेडिकल की एक छात्रा द्वारा अपने शिक्षक के खिलाफ की गई यौन उत्पीड़न की शिकायत पर समय पर कार्रवाई करने में विफल रहने को लेकर की थी। अदालत ने कहा कि ऐसी टिप्पणी से मेधेकर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। न्यायमूर्ति आर आई छागला और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने पिछले महीने पारित आदेश में कहा कि मेधेकर के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के कोई आरोप नहीं हैं और उनके खिलाफ एकमात्र शिकायत यह है कि छात्र की शिकायत पर वह समय पर कार्रवाई करने में विफल रहे। अदालत ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा मेधेकर को जारी किए गए चेतावनी मेमो को भी रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि एमआईसीसी की रिपोर्ट में मेधेकर के खिलाफ टिप्पणी और बीएमसी का चेतावनी मेमो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हैं, क्योंकि यह उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना जारी की गईं।

■ उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियों से याचिकाकर्ता (मेधेकर) की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। उच्च न्यायालय ने कहा कि मेधेकर के बारे में एक 'भ्रामक और प्रतिकूल धारणा' बनी, जिससे उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंची। मेधेकर ने सितंबर 2024 में मुख्य आंतरिक शिकायत समिति (एमआईसीसी) द्वारा उनके खिलाफ की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने और उन टिप्पणियों के परिणामस्वरूप उप नगर आयुक्त (जन स्वास्थ्य) द्वारा उन्हें जारी किए गए चेतावनी मेमो को रद्द करने का अनुरोध किया था। अक्टूबर 2024 में, मेधेकर को नायर अस्पताल के डीन के पद से स्थानांतरित करके हिंदूहृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे मेडिकल कॉलेज और आर एन कूपर अस्पताल भेज दिया गया। यह कार्रवाई एमआईसीसी के रुख अपनाने के बाद की गई कि अस्पताल के प्राधिकारियों, मुख्य रूप से डीन ने एमबीबीएस की द्वितीय वर्ष की एक छात्रा द्वारा एक वरिष्ठ मेडिकल शिक्षक के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत के प्रति 'असंवेदनशील' रवैया अपनाया। एमआईसीसी ने अपने निष्कर्षों में और बीएमसी ने अपने चेतावनी मेमो में यह राय व्यक्त की थी कि मेधेकर सहित नायर अस्पताल के प्राधिकारियों ने छात्रा द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं की और/या समय पर कार्रवाई करने में विफल रहे।

मुंबई में सड़क किनारे पेशाब करने से रोकने पर ली जान

बुजुर्ग महिला की बेरहमी से की हत्या

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

मुंबई के बांद्रा इलाके से एक बेहद चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। जहां सड़क किनारे पेशाब करने से रोकने पर आरोपी ने 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जान ले ली। इस मामले में खेरवाडी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 44 वर्षीय भानुदास कांबले के रूप में हुई है, जो ठाणे का निवासी बताया जा रहा है। उसे अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मृत महिला की पहचान सौभाग्यम्मा काठीम्युनर के तौर पर हुई है, जो धारावी के शाहूनगर इलाके में रहती थी। महिला के लापता होने की शिकायत पहले से ही शाहू नगर पुलिस थाने में दर्ज थी।

अचेत अवस्था में मिली थी महिला

पुलिस के मुताबिक, सुबह करीब 7 बजे स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि बांद्रा स्थित आरएनए बिल्डिंग के पास फुटपाथ पर एक बुजुर्ग महिला अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही खेरवाडी पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को सायन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में इसे आकस्मिक मौत मानते हुए एडीआर दर्ज किया गया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।

पोस्टमार्टम से गहराया शक

मामले ने उस वक्त गंभीर रूप लिया जब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला के सिर और माथे पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था, जिसके बाद गला दबाकर उनकी हत्या की गई। इसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। शुरूआती जांच में महिला की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई, इसलिए पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच के दौरान फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति घटना स्थल के पास पेशाब करते हुए दिखाई दिया। तकनीकी विश्लेषण और निगरानी के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की।

आरोपी ने कबूल किया अपराध

पूछताछ में आरोपी भानुदास कांबले ने बताया कि वह पेशे से इलेक्ट्रिशियन है और काम से लौटते वक्त सड़क किनारे पेशाब कर रहा था। इसी दौरान फुटपाथ पर सो रही महिला ने उसे ऐसा करने से रोका, जिससे नाराज होकर उसने पास पड़ी ईंट से महिला के सिर पर हमला किया और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

हिंदमाता एंकरः पर्याप्त सबूत भी नहीं, पर हथियार तस्करी के आरोप में आकिफ 20 वर्ष रहा जेल में बंद

अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के चर्चित औरंगाबाद हथियार तस्करी मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 44 वर्षीय सैयद आकिफ सैयद जफरुद्दीन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने जमानत देते समय मुख्य रूप से दो आधारों को ध्यान में रखाः पहला, आकिफ के खिलाफ अपराध में शामिल होने के पर्याप्त सबूतों की कमी और दूसरा, उसका पिछले 20 वर्षों से जेल में बंद होना। न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति श्याम सी. चांडक की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जो यह साबित करे कि आकिफ हथियारों और विस्फोटकों की खरीद या तस्करी में सीधे तौर पर शामिल था।

2006 का मामला

यह मामला मई 2006 का है, जब महाराष्ट्र एटीएस ने येवला-छत्रपति संभाजीनगर रोड पर छापेमारी कर 16 एके-47 राइफलें, 3200 कारतूस और 43 किलो आरडीएक्स जब्त किया था। एटीएस का दावा था कि यह भारी मात्रा में असलहा 2002 के गुजरात दंगों का बदला लेने और आतंकी साजिश रचने के लिए इकट्ठा किया गया था, जिसमें आकिफ को भी साजिशकर्ता बताया गया था।

आरोप को साबित करने के लिए नहीं पेश किए गए सबूत

आकिफ के वकील मुबीन सोल्कर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को हथियारों के परिवहन की कोई जानकारी नहीं थी और न ही उसने किसी बड़ी आतंकी साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई थी।अदालत ने यह भी नोट किया कि अभियोजन पक्ष ने आकिफ की नेपाल यात्रा और एक कथित ईमेल के आधार पर उसे 'जिहाद' से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इन दावों के समर्थन में कानूनन पुख्ता सबूत पेश नहीं किए गए। खंडपीठ ने कहा कि आकिफ पहले ही 40 साल की संभावित सजा का आधा हिस्सा यानी 20 साल जेल में काट चुका है, इसलिए उसकी अपील लंबित रहने के दौरान उसे सलाखों के पीछे रखना उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने आकिफ को 2 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतें जमा करने पर रिहा करने का निर्देश दिया है।

विचार प्रवाह

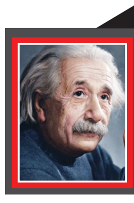

अपना जीवन जीने के केवल दो ही तरीके हैं। पहला यह मानना कि कोई चमत्कार नहीं होता है, दूसरा है कि हर वस्तु एक चमत्कार है। - **अल्बर्ट आईन्सटीन**

संपादकीय

मुस्लिम वोटिंग में बदलाव

बंगाल और असम सहित पांच राज्यों के चुनावी नतीजों ने न केवल सत्ता का संतुलन बदला है, बल्कि मुस्लिम राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले चेहरों के वजूद पर भी बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। मुस्लिम वोटों के सहारे किंगमेकर बनने का सपना लेकर चुनावी पिच पर उतरे हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा। देश में भले ही मुस्लिम मुस्लिम आबादी 15 फीसदी हो, लेकिन केरल में 27 फीसदी, असम और पश्चिम बंगाल में 30 से 35 फीसदी के बीच है। इस तरह तीनों ही राज्यों में मुस्लिम वोटर काफी अहम है, जिसके चलते ही मुस्लिम आधार वाले दल अपना सियासी दम दिखाने के लिए उतरे थे, लेकिन मुस्लिम वोटिंग पैटर्न अलग ही नजर आया। पश्चिम बंगाल से लेकर केरल और असम तक मुस्लिम मतदाता बीजेपी के खिलाफ एकजुट नजर आए, लेकिन मुस्लिम आधार वाले दलों पर भरोसा नहीं किया। इसी का नतीजा है कि असम में बदरुद्दीन अजमल धराशाही हो गए तो बंगाल में हुमायूं कबीर अपनी सीट के सिवा किसी दूसरी सीट पर कुछ खास नहीं कर सके। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का खाता तक नहीं खुल सका। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। बीजेपी के पक्ष में बहुसंख्यक वर्ग एकजुट रहा तो मुस्लिम मतदाता एकजुट हुए, लेकिन मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी,अब्बास पीरजादा सहित कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के बजाय ममता के पक्ष में वोटिंग करना बेहतर समझा। इसका नतीजा रहा है कि टीएमसी मुस्लिम बहुल वाली ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। राज्य की 100 से ज्यादा सीट पर मुस्लिम वोटर्स अहम हैं। मुस्लिम वोटों की सियासी ताकत को देखते हुए पहले फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेकुलर फ्रंट से पार्टी बनाई है तो इस बार हुमाऊं कबीर ने बाबर के नाम पर मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाने का ऐलान कर मुस्लिम सियासत का चेहरा बनने का दांव चला। हुमाऊ कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाकर मैदान में उतरे थे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुस्लिम वोटों पर दांव चला था। 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में नौशाद सिद्दीकी, हुमाऊं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मैदान में थी। हुमाऊ कबीर बाबरी के बहाने बंगाल में मुस्लिमों का विश्वास जीतने का दांव चला, लेकिन मुसलमानों ने ममता के साथ ही खड़े होना बेहतर समझा। हुमायूं कबीर की पार्टी दो सीटों पर जीत मिल रही है, जिन सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। नौदा और रेजनीनगर सीट पर उन्हें बढ़त है, जो जीत में तब्दील हो सकती है। इसी तरह नौशाद सिद्दीकी को सिर्फ एक सीट पर बढ़ता है, जो एसआईएफके टिकट पर चुनाव लड़ रहे। बंगाल के मुस्लिमों ने एकमुश्त टीएमसी को दिया था। इसी का नतीजा है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम आधार वाले दलों का ही नहीं बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट का सफाया हो गया था। ममता बनर्जी के पक्ष में खुलकर मुसलमानों ने वोट दिया है।हुमाऊं कबीर और अब्बास सिद्दीकी के साथ ओवैसी को मुस्लिमों ने पूरी तरह नकारा दिया। ओवैसी की पार्टी को 0.10 फीसदी वोट शेयर मिले तो हुमायूं व अब्बास की पार्टी को भी आधा फीसदी वोट नहीं मिल सका। असम में बदरुद्दीन की सियासी चुनौती असम में मुस्लिम वोटों की राजनीतिक अहमियत को देखते हुए मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) का गठन 2005 में किया। अजमल ने अपनी राजनीति मुस्लिम अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से असमिया भाषी और बंगाली मूल के मुसलमानों के अधिकारों के हिमायती के तौर पर शुरू की और 2009 से 2024 तक धुबरी से सांसद रहे। साल 2006 के विधानसभा चुनाव में एआईयूडीएफ के पास 10 विधायक जीते थे, 2011 में बढ़कर 18 विधायक हो गए। 2016 में 13 सीटों पर कामयाबी मिली फिर 2021 में 16 सीटों पर जीत मिली। इस तरह से हर साल, एआईयूडीएफ का जनाधार बढ़ा और पार्टी मजबूत हुई है,लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बदरुद्दीन अजमल की राजनीति को गहरा झटका लगा, जब वो अपनी ही सीट हार गए। कांग्रेस दोबारा से मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ बनाती नजर आई। इसक चलते 2026 के असम चुनाव में सिर्फ दो सीट पर ही सिमट गई। मुस्लिम मतदाताओं ने महसूस किया कि अलग-अलग धार्मिक पार्टियों को वोट देने से भाजपा के खिलाफ लड़ाई कमजोर होती है। उन्होंने छोटे दलों के बजाय बड़े चेहरों पर दांव लगाया।

आज का इतिहास

- 1919 - पेरिस में रेडक्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गयी थी।
- 1920 झ अधिकारियों ने कथित चोरी और हत्या के लिए निकोला साको और बाटोलोमो वानजेटी को गिरफ्तार किया था।
- 1922 - ब्रोंक्स में यांकी स्टेडियम का निर्माण शुरू हुआ था।
- 1925 - दक्षिण अफ्रीका सरकार ने अफ्रीकी को आधिकारिक भाषा घोषित किया था।
- 1927 - वर्जीनिया वूल्फ द्वारा लाइटहाउस को पहली बार प्रकाशित किया गया था।
- 1940 - द्वितीय विश्व युद्धः नॉर्वेजियन शरणार्थियों ने लंदन में एक सरकारी निर्वासन का निर्माण किया था।
- 1944 - जर्मन सैनिकों ने ग्रीस के क्लेसौरा गांव में 216 नागरिकों को निष्पादित किया था।
- 1950 - भुमबोल अदुलदेज को थाईलैंड के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था।
- 1961 - बुध कार्यक्रमः बुध-रेडस्टोन 3ः एलन शेपर्ड एक पूर्व-कक्षीय उड़ान पर बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला अमेरिकी बन गया था।
- 1964 - यूरोप की परिषद ने 5 मई को यूरोप दिवस के रूप में घोषित किया था।
- 1972 - एलीटालिया फ्लाइट 112 पालेर्मो, सिसिली के पास माउंट लोंगा में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी जिसमे 115 लोगों की मौत हो गई थे।
- 1987 - ईरान-कॉन्ट्रा संबंधः संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस की टेलीविजन सुनवाई शुरू हुई थी।
- 1994 - अमेरिकी किशोरी माइकल पी फे को चोरी और बर्बरता के लिए सिंगापुर में डिब्बाबंद किया गया था।
- 2014 - हांगकांग के तट पर मार्शल द्वीप पंजीकृत कंटेनर जहाज के साथ चीनी कार्गो जहाज टकराव के बाद 11 लोग गायब हो गए थे।
- 2014 - ग्रीस के तट पर एजियन सागर में शरणार्थियों की टक्कर हुई बीस लोग मारे गए थे।

डिजिटल युग में सुनना सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक कौशल क्यों है?

अध्ययन

हिंदमाता डेस्क @ मुंबई

डिजिटल युग में यह समझना कठिन नहीं है कि किसी बातचीत के दौरान लोग कब वास्तव में सुनना बंद कर देते हैं। उनकी नजरें भटकने लगती हैं, प्रतिक्रिया बहुत जल्दी आ जाती है, या पास रखी स्क्रीन की ओर ध्यान खिंच जाता है। बातचीत चलती रहती है, लेकिन संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पहले ही खो चुका होता है। आज हम पहले से कहीं अधिक विभिन्न मंचों, उपकरणों और डिजिटल स्थानों पर एक-दूसरे से बात करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम वास्तव में एक-दूसरे को सुन भी रहे हैं? सार्वजनिक बहसें आज मुख्य रूप से बोलने पर केंद्रित हैं—कौन बोल सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या सीमाएं होनी चाहिए, और क्या मुक्त अभिव्यक्ति खतरे में है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लेकिन ये इस बुनियादी धारणा पर आधारित हैं कि बोलना अपने आप में सुने जाने की गारंटी है—जिस पर बहुत कम विचार किया जाता है। प्राचीन एथेंस वासियों के संदर्भ का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उस समय लोकतांत्रिक संवाद दो समान तत्वों पर आधारित माना जाता था—बोलने का अधिकार और सत्य बोलने का साहस। लेकिन ये दोनों ही तब तक सार्थक नहीं होते जब तक कोई ऐसा श्रोता मौजूद न हो जो वास्तव में बात को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। अर्थात बोलना और सुनना प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अभ्यास के दो पूरक हिस्से हैं, और एक के बिना दूसरे की रक्षा संभव नहीं है।

सुनना कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है

आज स्थिति यह है कि बोलने के अधिकार को विस्तार देने पर तो बहुत ध्यान दिया गया है, लेकिन यह समझने पर बहुत कम ध्यान दिया गया है कि जब कोई बोलता है तो सामने वास्तव में क्या हो रहा होता है। सुनना कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। यह केवल चुप रहकर सुनने जैसा नहीं है और न ही यह केवल शब्दों को ग्रहण करना है। अच्छी तरह सुनने का अर्थ है किसी व्यक्ति के कथन को एक अर्थपूर्ण बात के रूप में स्वीकार करना, उसे समझना, उसकी व्याख्या करना और फिर उस पर प्रतिक्रिया देना।दार्शनिक इसे अपटेक कहते हैं—यानी प्रतिक्रिया देने से पहले यह इच्छा कि सामने वाले की बात को सही ढंग से ग्रहण किया जाए।

किसी तर्क को पूरी तरह समझने के लिए उसे पर्याप्त समय दें

व्यावहारिक रूप में इसका अर्थ है कि किसी तर्क को पूरी तरह समझने के लिए उसे पर्याप्त समय देना, न कि उसके विकृत या सरल संस्करण पर प्रतिक्रिया देना। इसका मतलब यह भी है कि यह समझना कि किसी व्यक्ति ने वास्तव में क्या कहा है और हमने यह मानकर क्या समझ लिया है, दोनों में फर्क है। यह भी महत्वपूर्ण है कि बोलने वाले व्यक्ति को किसी बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक साझा संवाद के सहभागी के रूप में देखा जाए। लेकिन यह अपेक्षा जितनी सरल लगती है, उतनी है नहीं। आमतौर पर लोग सुनते समय समझने के बजाय जवाब देने की तैयारी कर रहे होते हैं। वे तर्क की कमजोरी, विरोध के अवसर या अपने विचार रखने का मौका खोजते रहते हैं। यह सुनना नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करना है।

... तो सार्वजनिक बहस शोर में बदल जाती है

लोकतांत्रिक जीवन में यह अंतर बेहद महत्वपूर्ण है। जब नागरिक किसी विरोधी विचार को उसके वास्तविक रूप में समझने के बजाय उसके विकृत रूप पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो सार्वजनिक बहस शोर में बदल जाती है। ऐसी स्थिति में असहमति एक प्रदर्शन बन जाती है, तर्क एक नाटकीय प्रस्तुति में बदल जाता है और वास्तविक संवाद की संभावना धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। जिन डिजिटल मंचों पर आज सार्वजनिक संवाद होता है, उन्हें सुनने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि संवाद के लिए बनाया गया है।

विचारशील और संतुलित सामग्री अक्सर पीछे रह जाती है

यह संवाद क्लिक, शेयर, प्रतिक्रिया और स्क्रीन पर बिताए गए समय से मापा जाता है। ऐसे में जो सामग्री तीव्र भावनाएं—जैसे गुस्सा, आक्रोश या नैतिक चिंता—उत्पन्न करती है, वह अधिक फैलती है। जबकि विचारशील और संतुलित सामग्री अक्सर पीछे रह जाती है। इसके परिणामस्वरूप एक ऐसा सूचना वातावरण बनता है जो तेज, सीधे, भावनात्मक और प्रतिक्रिया-उन्मुख संचार को बढ़ावा देता है—जो सुनने की प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। इसके अलावा, एल्गोरिदम लोगों तक विचारों को उनके पूरे संदर्भ में नहीं पहुंचाते। अधिकतर लोग तर्कों के टुकड़े, स्क्रीनशॉट, संक्षेप या तोड़े-मरोड़े गए अंशों के माध्यम से विचारों से परिचित होते हैं। ये अंश अक्सर इसलिए चुने जाते हैं ताकि उन्हें आसानी से खारिज किया जा सके या मजाक का विषय बनाया जा सके। इस प्रकार लोग वास्तविक विचारों के बजाय उनके कार्टून रूप से संवाद करने लगते हैं, जिसमें सुनने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है।

नागरिक स्तर पर ही खोजना होगा समाधान

ऐसे वातावरण का लोकतांत्रिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। एक ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र जहां लोग लगातार बोलते हैं लेकिन महसूस करते हैं कि उन्हें सुना नहीं जा रहा, वह स्वस्थ लोकतंत्र नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में असंतोष बढ़ता है, विचार और कठोर होते जाते हैं, और सामूहिक निर्णय के लिए आवश्यक साझा आधार कमजोर पड़ता जाता है। यह समस्या केवल तकनीक की नहीं है, बल्कि नागरिक समाज की है और इसका समाधान भी नागरिक स्तर पर ही खोजना होगा। अच्छी बात यह है कि सुनना, एल्गोरिदम की तरह जटिल नहीं, बल्कि एक सीखा जाने वाला कौशल है। शिक्षा के क्षेत्र में इसे अभ्यास के रूप में विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, छात्रों को यह निर्देश दिया जा सकता है कि वे किसी सहपाठी के तर्क की आलोचना करने से पहले उसे उसकी संतुष्टि के अनुसार सही ढंग से दोहराएं।

आलोचना करने से पहले विचार के मूल को समझें

इसी तरह यह अभ्यास भी कराया जा सकता है कि किसी भी लेख, वीडियो या पॉडकास्ट को सुनने के बाद पहले उसका तर्क निष्पक्ष रूप से समझाया जाए और फिर उस पर राय दी जाए। यह अभ्यास केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। रोजमर्रा के जीवन में भी इसे अपनाया जा सकता है—किसी प्रतिक्रिया देने से पहले यह जांचना कि क्या आप वास्तव में बात को समझ चुके हैं। किसी विचार की आलोचना करने से पहले उसे उसके मूल स्वरूप में प्रस्तुत करना, और व्यक्ति के कथन को उसकी अपनी भाषा में समझना—ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। केवल बोलने की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधा हिस्सा है। प्राचीन यूनान में अगोरा केवल एक मंच नहीं था, बल्कि विचारों के आदान-प्रदान का स्थान था। उसी भावना को आज के डिजिटल, शैक्षिक और सामाजिक वातावरण में पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। और इसकी शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि एक शांत और अधिक कठिन कौशल से होती है। यह कौशल सुनना है।

सिनेमा से सियासत के जननायक तक!

हिंदमाता डेस्क @ मुंबई

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को काउंटिंग चल रही है। रुझानों को अगर देखें तो वे राज्य में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। जिस तमिलनाडु की सत्ता पर हमेशा से द्रविड मुनेत्र काषगम और अन्नाद्रुमक का कब्जा था, वहां आज एक्टर से राजनेता बने जोसेफ विजय चंद्रशेखर की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) इतिहास रचने जा रही है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 110 पर टीवीके आगे चल रही है। रुझानों से विजय का वह नारा सच होता नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था- विजय आएगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते समय कई बार उन्होंने यह नारा लगाया। अब सबके मन में यही सवाल है कि विजय ने कैसे वो कर दिखाया जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के रजनीकांत और कमल हसन जैसे सुपरस्टार नहीं कर सके। फैन फॉलोइंग तो इनकी भी बहुत तगड़ी है तो आखिर विजय ने ऐसा क्या किया, जिसकी वजह से वह सिर्फ अभिनेता ही नहीं राजनेता के तौर पर भी तमिलनाडु की जनता के दिलों में उतर गए। विजय से पहले रजनीकांत और कमल हसन की बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों भगवान की तरह पूजे जाने वाले इन एक्टर्स को चुनावों में लोगों का प्यार नहीं मिला। रजनीकांत ने साल 2017 में राजनीति में आने का ऐलान किया, लेकिन सालों तक उन्होंने इस तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। फिर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर कदम पीछे खींच लिए। वहीं, कमल हसन ने पूरी प्लानिंग के साथ राजनीति में कदम रखा। साल 2018 में अपनी पार्टी भी बनाई, जिसका नाम मक्कल नीधि मय्यम है। कमल हसन जनता के बीच काफी एक्टिव भी नजर आए, लेकिन उनकी राजनीति और भाषण लोगों को उनकी तरफ उतना खींच नहीं पाए। उधर, उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने के लिए कार्यकर्ताओं की भी कमी थी, जिस कारण वे कोई बड़ा चुनावी प्रभाव नहीं बना सके। रजनीकांत और कमल हसन की इन गलतियों से विजय ने काफी कुछ सीखा और उन्होंने धीरे-धीरे जनता में राजनेता के तौर पर अपनी पकड़ बनाने के लिए काम किया। सालों तक एक मजबूत पिच तैयार की। विजय ने अपने फैन क्लब- विजय मक्कल इयक्कम के साथ उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ काम किया। उनके क्लब के ये फैंस सालों से ब्लड डोनेशन, मुफ्त भोजन वितरण और आपदा राहत जैसे सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं।

रजनीकांत और कमल हसन जो नहीं कर पाए, विजय ने कर दिखाया

युवाओं और छात्रों पर विजय का फोकस

विजय ने युवाओं और छात्रों पर भी फोकस रखा। उन्होंने राज्य के बोर्ड एग्जाम टॉपर्स को सम्मानित करने के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम शुरू किया, जहां उन्होंने भाषण में छात्रों से पैसे लेकर वोट न डालने की अपील की। इस तरह मिडिल क्लास में उनकी छवि अच्छी बनी और जो लोग उनकी एक्टिंग के फैन थे, उन्होंने राजनेता के तौर पर भी उन्हें स्वीकार किया।

युवाओं, महिलाओं और मछुआरों पर ध्यान

टीवीके के मेनिफेस्टो में भी युवाओं, महिलाओं और मछुआरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पार्टी का मानना है कि ये तीन वर्ग चुनावों का रुख बदल सकते हैं। पार्टी ने पहली बार आठ तरह की मछली की किस्मों के लिए अपनी तरह के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) का भी ऐलान किया, जिसके तहत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान 27 हजार रुपए की राहत राशि, सबसिडाइज्ड डीजल, बीमा कवरेज और आवास की सुविधा दी जाएगी।

तमिलनाडु की नब्ज को समझने में कामयाब रहे

टीवीके ने 12वीं से लेकर हायर एजुकेशन जिसमें पीएचडी प्रोग्राम भी शामिल है, के लिए 25 लाख रुपए तक बिना गारंटी वाले एजुकेशन लोन का भी प्रस्ताव रखा। महिलाओं के लिए भी कई ऐलान किए गए, जैसे सालाना छह फ्री एलपीजी सिलेंडर, मासिक वित्तीय सहायता में 1000 रुपए से 2500 रुपए तक की बढ़ोतरी और विवाह सहायता योजनाओं के तहत आठ ग्राम तक सोना उपलब्ध करवाना। ऐसा लगता है कि विजय तमिलनाडु की नब्ज को समझने में कामयाब रहे।

प्रेरक प्रसंग

ईमानदारी अनमोल है

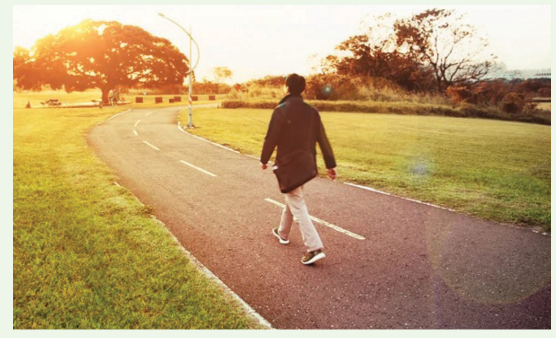

झेन चेंग एक उपकरण मरम्मत की दुकान का मालिक था। वह दयालु, ईमानदार था और कायदे से कारोबार करता था। वह कभी किसी की आँखों में धूल झोंकने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि वह अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए मुश्किल से ही पैसा कमा पा रहा था। कुछ समय बाद, उसके परिवार के सदस्य और एक साथी व्यापारी ने उसे कारोबार के हथकंडों को आजमाने के लिए उकसाया, और झेन चेंग उस कहावत पर विश्वास करने लगा जो एक शैतानी सिद्धांत को दर्शाती है: "बिना दूसरी आमदनी के आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता, जैसे कि घोड़ा अगर रात में अपने तबेले में भूखा रहेगा तो कभी उसका वजन नहीं बढ़ेगा।" "मजबूत आदमी खा-खा कर मरता है; और कमजोर आदमी भूख से," "पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन इसके बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।" और "पैसा सबसे पहले है।" झेन चेंग ने अपने उस अच्छे विवेक को खो दिया जिसने पहले उसका पथ-प्रदर्शन किया था और वह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के गलत तरीकों को इस्तेमाल करने लगा। यूँ तो उसने पहले से ज्यादा पैसा कमाया, और उसके जीवन स्तर में भी इजाफा भी हुआ, लेकिन झेन चेंग नाखुश था और खालीपन महसूस कर रहा था; जीवन खोखला और कष्टों से भरा हुआ था।

जब झेन चेंग ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार किया, उसको परमेश्वर के वचन से यह समझ में आ गया कि परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम करते हैं और धोखा देने वालों से घृणा करते हैं। झेन चेंग को यह भी समझ आ गया कि सिर्फ ईमानदार व्यक्ति होना ही एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार करने का और परमेश्वर की प्रशंसा पाने का एकमात्र रास्ता है, इसलिए उसने एक ईमानदार व्यक्ति बनने की कसम खा ली। हालाँकि, असल जीवन में ईमानदार होना बहुत ही कठिन सिद्ध हुआः कलीसिया में भाइयों और बहनों के साथ, वह साफ-साफ कहने वाला व्यक्ति था जैसा कि उसको होना भी चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा ही व्यवहार वह अपने कारोबार में भी करता, तो क्या वह ज्यादा पूंजी बना पायेगा? शायद वह सिर्फ कम पैसा ही नहीं बनाएगा, बल्कि कुछ और भी नुकसान उठा सकता है और शायद उसकी दुकान भी बंद हो सकती है......इन सब परेशानियों को झेलते हुए, क्या झेन चेंग अपने कारोबार को ईमानदारी के साथ चला सकेगा? क्या कुछ अनचाहे मोड़ और परिवर्तन इस प्रक्रिया में आयेंगे? उसका सबसे बड़ा इनाम क्या होगा?...

राशिफल

मेष– आज के दिन ऑफिस लाइफ प्रोडक्टिव रहेगी और कई अवसर सामने आ सकते हैं। आज प्रेमी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। आर्थिक रूप से, आप अच्छा करेंगे। आज आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कानूनी विवाद जीत सकते हैं।

वृषभ– आज के दिन सुनिश्चित करें कि आपका प्रेम संबंध बरकरार रहे और इस सप्ताह आपके जीवन को प्रभावित करने वाली कोई बड़ी व्यावसायिक समस्या न हो। संतुलित आहार लें और धन भी सकारात्मक है।

मिथुन– आज के दिन प्रेम संबंधों को और भी मजेदार बनाने के लिए कुछ बातों पर विचार करें। आज काम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए विकल्पों पर विचार करें। कठोर वित्तीय निर्णय लें। आज स्वास्थ्य भी अच्छा है।

कर्क– आज के दिन लव के मामले में अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। आपको ऑफिस में सीनियर्स की एक्सपेक्टेशन को भी पूरा करना चाहिए। धन को सही तरीके से संभालें। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

सिंह– आज के दिन प्रेम जीवन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। प्रेम और ऑफिस दोनों ही जीवन में वाद-विवाद से बचना अच्छा रहेगा। आज के दिन आपका धन और संपदा का मामला दोनों ही अच्छा है।

कन्या– आज के दिन स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। रोमांटिक कनेक्शन मजबूत होगा। आपका प्रोफेशनल जीवन सफल रहेगा। विभिन्न विकल्पों में निवेश करने के लिए ये दिन अच्छा रहेगा। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी।

तुला– आज के दिन प्रेम संबंधों में आश्चर्य की उम्मीद करें और काम में पूरी तरह समर्पित रहें। आपके स्वास्थ्य के साथ-साथ धन में वृद्धि के विकल्प भी हैं। रोमांस से भरपूर दिन बीतेगा। प्रोफेशनल लाइफ को बिजी और प्रोडक्टिव बनाए रखें।

वृश्चिक– आज के दिन प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव को दूर करें और नए काम हाथ में लें, जिससे करियर में तरक्की होगी। पैसों से जुड़ी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अपने रिलेशन को पॉजिटिव बनाए रखें।

धनु– आज के दिन कोई गंभीर मेडिकल समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। विभिन्न स्रोतों से धन भी आएगा। प्यार में खुश रहें और सभी प्रकार के वाद-विवाद से बचें। ऑफिस में आपका प्रदर्शन तारीफ का पात्र रहेगा।

मकर– आज के दिन समृद्धि आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। आप स्वस्थ भी रहेंगे। प्यार के मामले में शांत रहें। ध्यान रखें किसी पिछली घटना से संबंधित कोई वाद-विवाद न हो। आपका अनुशासन आपके सीनियर्स का दिल जीत सकता है।

कुंभ– आज के दिन धन का प्रवाह होगा, जिससे आप महत्वपूर्ण फैसले ले सकेंगे। छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। पार्टनर पर स्नेह बरसाएं और यह रिश्ते में झलकेगा। ऑफिस से जुड़े मामलों को संभालते समय शांत रहें।

मीन– आज के दिन ऑफिस में आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। समृद्धि आएगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। टीम को संभालते समय सावधान रहें क्योंकि अहंकार से जुड़े छोटे-मोटे मुद्दे लीडरशिप स्किल्स पर असर डाल सकते हैं। अच्छी कमाई हो सकती है।

भाजपा का 'जय मां काली' सुपरहिट, टीएमसी का 'हृदय माछे काबा, नयन-ए-मदीना' फुस्स

हिंदमाता नेटवर्क @ जबलपुर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने शुरू हुए तो रुझानों के बाद से ही देश भर में एक गाने की खूब चर्चा होने लगी। हालांकि, इस गाने ने चुनाव प्रचार के दौरान भी खूब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाई थी। बांग्लादेश के मशहूर कवि अब्दुल रहमान बोयाती, जो अविभाजित बंगाल में पैदा हुए थे, उनका एक लोकगीत 'हृदय माछे काबा, नयन-ए-मदीना' मानो बंगाल की सियासत के केंद्र में हो, अभिनेत्री से नेता बनी सयानी घोष ने चुनाव प्रचार के दौरान इस लोकगीत को मुस्लिम बहुल इलाकों में रैलियों के दौरान गाकर राजनीतिक सनसनी फैला दी थी। इस पर बंगाल चुनाव के दौरान खूब राजनीतिक बहस हुई और अब इसका नतीजा टीएमसी को भुगतना पड़ा। दरअसल, भाजपा ममता बनर्जी की टीएमसी पर जो चुनाव प्रचार के दौरान तृष्टीकरण की राजनीति का इल्जाम लगा रही थी। सयानी के मंच से गाए जा रहे इस गाने 'हृदय माछे काबा, नयन-ए-मदीना' को जनता ने उसी का प्रतिबिंब मान लिया। ऐसे में ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में मां, माटी और मानुष का नारा भी इस बार इसके आगे कुछ काम नहीं आया और भाजपा टीएमसी को इस बार घेरने में कामयाब रही। बंगाल के चुनाव में इस बार मां, माटी और मानुष के नारे के साथ ही महिला सुरक्षा, घुसपैठिया, वोटर सत्यापन, जय बांग्ला बनाम जय श्रीराम का नारा गूंजता रहा। लेकिन, इस सबके बीच 'हृदय माछे काबा, नयन-ए-मदीना' ने जो सेंध टीएमसी को लगाई उससे संभलने के लिए अब उसे 5 साल का इंतजार करना होगा। दरअसल, काली की भूमि से काबा का नारा पश्चिम बंगाल के वोटरों को रास नहीं आया। दुर्गा पूजा के पंडाल में ममता की उपस्थिति में भी यही गाना गाया गया था, तब से लेकर अब चुनावी रैलियों में जिस तरह से टीएमसी के नेता इसको चुनावी नारे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, उसको पचा पाना राज्य की जनता के लिए थोड़ा मुश्किल था। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद जश्न के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, "गंगा जी बिहार से होकर बंगाल तक बहती हैं। बिहार की जीत ने पश्चिम बंगाल में विजय का रास्ता खोल दिया है।" मतलब, गंगा जहां से निकलती है यानी उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल में गंगा सागर जहां गंगा समुद्र में मिलती है। वहां तक की सत्ता पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। हिंदुत्व की राजनीति पश्चिम बंगाल की जनता को भी पसंद आ गई और वह भाजपा के साथ हो गई।

■ इस बार के पश्चिम बंगाल चुनाव में स्थानीय मुद्दों से ज्यादा धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर नैरेटिव तैयार किए गए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने टीएमसी के इस गाने 'हृदय माछे काबा, नयन–ए–मदीना' को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश की और वह इसमें सफल भी रही। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे भाजपा के स्टार प्रचारकों ने इसे पश्चिम बंगाल में 'काली बनाम काबा' के रूप में पेश किया। उनका कहना था कि टीएमसी के दिल में काबा–मदीना हो सकता है, लेकिन बंगाल की आत्मा में मां काली और मां दुर्गा का वास है।

■ इस बार के चुनाव में भाजपा ने 'जय श्री राम' के साथ–साथ 'जय मां काली' के नारे को भी प्रमुखता से आगे बढ़ाया। भाजपा टीएमसी पर यह आरोप लगाती रही कि 'बंगाली अस्मिता' की बात करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी वास्तव में काबा और मदीना को बंगाल पर थोपने का प्रयास कर रही है।

पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में बंगाली पहचान का हिस्सा 'माछ और भात' भी छाया रहा। पुरुलिया में ममता बनर्जी ने एक सभा के दौरान कहा था, "अगर भाजपा सत्ता में आई, तो वे आपको मछली, मांस और अंडा नहीं खाने देंगे। भाजपा एक 'शाकाहारी संस्कृति' वाली पार्टी है, जो माछ–भात बंगाली की अस्मिता को खत्म करना चाहती है।"

■ भाजपा ने ममता के इस वार का जवाब दिया और बंगाल में पार्टी के नेताओं ने 'शाक्त परंपरा' (शक्ति की पूजा) का दामन थामा। अनुराग ठाकुर और मनोज तिवारी जैसे दिग्गज नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मछली खाकर यह संदेश दिया कि वे बंगाली संस्कृति के विरोधी नहीं हैं। कई क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान हाथ में मछली लेकर जुलूस निकाला।

■ महिला वोटर इस चुनाव के दौरान दोनों ही पार्टियों के केंद्र में रहीं। महिला वोटर्स को साधने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने महिलाओं के लिए पहले से चल रही 'लक्ष्मीर भंडार' योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली 1,000 रुपए की राशि को ठीक चुनाव से पहले फरवरी में बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया है।

सनातन का अपमान और हिंदी से दूरी स्टालिन-उदनिधि को ले 'डूबी'

वादों ने ऐसे महा 'वजिय' के करीब 'थलपति' को पहुंचाया

हिंदमाता नेटवर्क @ तमिलनाडु

तमिलनाडु में जिस तरह की सियासी राजनीति लंबे समय से चली आ रही थी, उस पर अब पूरी तरह से विराम लगता नजर आ रहा था। अपनी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को कंप्लीट करने और राजनीति में फुल टाइम एंट्री की घोषणा करने वाले एक्टर विजय तमिलनाडु की राजनीति में 'जननायक' बनकर उभरे हैं। इस राज्य का सियासी समीकरण हमेशा दो सिनेमाई दिग्गजों के परिवारों के बीच ही घूमता नजर आया। एम करुणानिधि और जे। जयललिता की पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के बीच ही लंबे समय से सत्ता का हस्तांतरण होता रहा। वहां कई और सिनेमाई दिग्गजों ने राजनीति में पैर पसारने की कोशिश की, लेकिन वह या तो सफल नहीं रहे या फिर चुनावी राजनीति में आने के ख्याल के बाद खुद ही उससे अपने को अलग कर लिया। लेकिन, इस बार तमिल सुपरस्टार 'थलपति' विजय ने डीएमके और एआईडीएमके की दो पक्षीय लड़ाई की दिशा मोड़कर रख दी है। उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) ने ऐसा कमाल किया है, जिसने करीब 50 साल पहले एमजी रामचंद्रन (एमजीआर) के करिश्मे की याद दिला दी। 234 सीटों वाली विधानसभा में थलपति विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (टीवीके) 100 सीटों से ज्यादा पर लीड कर रही है। यह आंकड़ा ऐतिहासिक है क्योंकि विजय ने यह करिश्मा 'अकेले शेर' की तरह किया है। उन्होंने अपनी लोकप्रियता के दम पर डीएमके के कैडर आधारित मजबूत संगठन वाली पार्टी और दूसरी तरफ एआईडीएमके के जमीनी चैलेंज को ध्वस्त कर दिया है। फिल्मों के 'कमांडर' रहे विजय ने अपनी रणनीतिक बढ़त से सबको चौंकाते हुए चेन्नई की पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली (पूर्व), दोनों ही विधानसभा सीटों पर जबरदस्त बढ़त बना रखी है। 2026 का यह विधानसभा चुनाव तमिलनाडु की राजनीति में बड़े बदलाव का सूचक बना है। इस चुनाव में जनता ने मतदान के जरिए दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच राज्य की पारंपरिक सत्ता संरचना को तोड़ दिया और तमिलनाडु के राजनीतिक जमीन पर सिने स्टार और टीवीके प्रमुख थलपति विजय की शानदार एंट्री का रास्ता खोल दिया। 2021 में सत्ता में आई डीएमके तमिलनाडु में अब सत्ता से दूर होती नजर आ रही है।

■ तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने इस बार पूरा चुनावी अभियान 'हिन्दी' विरोध और 'द्रविड़ पहचान' पर केंद्रित कर दिया था। जो वहां की जनता को पसंद नहीं आया। वैसे 'हिन्दी विरोध' तमिलनाडु की राजनीति का नया मुद्दा नहीं है। राज्य में भाषा और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति लंबे समय से चल रही है। डीएमके तो इसी विचारधारा के साथ राज्य की राजनीति में आई ही थी। लेकिन इस बार उसका हिन्दी विरोध का मुद्दा नहीं चल पाया। वहां स्वतंत्रता के बाद हुई सबसे ज्यादा वोटिंग ने यह साबित कर दिया कि वहां के युवा और शहरी मतदाता पुरानी द्रविड़ियन राजनीति में अब दिलचस्पी नहीं रखते हैं और गवर्नेंस, रोजगार, शिक्षा और डीएमके शासन से मुक्ति चाहते हैं।

■ सीएम एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान भी राज्य में डीएमके की नैया डुबोने में नंबर एक पर रहे। एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने 2023 में सनातन विरोधी एक बयान दिया था और पूरे देश के राजनीतिक हलके में इसकी चर्चा जोरों पर रही थी। 2 सितंबर 2023 को तमिलनाडु में आयोजित एक कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने कहा था, ₹सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विचार है, इसे खत्म करना मानवता और समानता को बढ़ावा देना है।

■ अपने बयान में उदयनिधि ने आगे कहा था, ₹जिस तरह हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरह सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है। इसे समाज से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए।

■ उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर पूरे देश में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई, उन पर मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन उदयनिधि ने नवंबर 2023 में फिर कहा, ₹मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है।

'यह जीत विकास, नारी शक्ति और 'विकसित असम' की परिकल्पना के पक्ष में - सीएम हिमंता बिस्वा सरमा

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

असम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में आने की हैट्रिक लगाने जा रही है। रुझान में असम में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है। इस बीच असम में भाजपा और सहयोगी दलों के शानदार प्रदर्शन पर हिमंता बिस्वा सरमा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ₹जनता का आशीर्वाद, तीसरी बार, विकास और विरासत के लिए, असम की जनता ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। यह हमारे कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों, जिनका नेतृत्व अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प के बिना संभव नहीं हो पाता।₹ उन्होंने आगे लिखा, "यह जीत विकास, नारी शक्ति, अस्मिता और एक 'विकसित असम' की परिकल्पना के पक्ष में दिया गया जनादेश है। यह विशाल जनादेश जनता के मिजाज को दर्शाता है, बराक से लेकर ब्रह्मपुत्र तक और ऊपरी असम से लेकर निचले असम तक, जिन्होंने विकास और अस्मिता के विमर्श के साथ पूरी दृढ़ता से खड़े रहने का निर्णय लिया है। अत्यंत विनम्रता के साथ, हम जनता के आशीर्वाद के समक्ष नतमस्तक हैं और 'विकसित एवं सुरक्षित असम' के हमारे आह्वान पर उन्होंने जो जोरदार समर्थन दिया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। असम को भारत के शीर्ष 5 राज्यों में शुमार करने के हमारे अथक प्रयास, आज से और भी अधिक जोर-शोर से जारी रहेंगे।" इससे पहले सीएम सरमा ने एक्स पर लिखा, "शतक के साथ हैट्रिक।" चुनाव आयोग के अनुसार, असम में 126 विधानसभा सीटों में से एनडीए 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 82 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जिसमें 51 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, वहीं 31 सीटों पर आगे चल रही है। एनडीए में शामिल अन्य दल, एजीपी को 10 सीटों पर आगे है, जिसमें 3 पर जीत और 7 सीट पर आगे चल रही है। वहीं बीपीएफ 10 सीट पर आगे चल रही है, जिसमें 6 सीट पर उसे जीत और 4 सीट पर आगे है। इसके अलावा कांग्रेस 19 सीटों पर आगे है, जिसमें एक सीट पर पार्टी को जीत मिली है, जबकि 18 सीटों पर आगे है।

हरियाणा : एचपीजीसीएल के वित्त निदेशक अमित दीवान बर्खास्त

घोटाले का आरोप

हिंदमाता नेटवर्क @ दक्षिण कोरिया

हरियाणा सरकार ने वित्तीय घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एचपीजीसीएल (हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड) के वित्त निदेशक अमित दीवान को बर्खास्त कर दिया है। उन्हें हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 18 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था जिसके बाद से वे सस्पेंड चल रहे थे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तथा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंकों के खातों के संचालन में अनियमितता तथा धोखाधड़ी के मामले में सरकार के आदेश पर हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एफआईआर दर्ज करवाते हुए इस मामले की जांच शुरू की गई थी। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि यह मामला एक सुनियोजित और बहु-स्तरीय वित्तीय घोटाले से जुड़ा है, जिसमें सरकारी प्रक्रियाओं में हेरफेर कर फर्जी बैंकिंग लेन-देन के माध्यम से सरकारी धन को आरोपी एवं उनके सहयोगियों से जुड़ी संस्थाओं और खातों में स्थानांतरित किया गया। इस मामले की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि अमित दीवन ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए आरोपित व्यक्तियों एवं बैंक अधिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए और एचपीजीसीएल के हितों से समझौता कर अनुचित लाभ प्राप्त किया। अतः उक्त दोषी अधिकारी का आचरण पावर यूटिलिटीज के हितों के प्रतिकूल पाया गया है। इसके मद्देनजर सरकार द्वारा अमित दीवान को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

लिपुलेख मामले पर भारत ने नेपाल को दिया करारा जवाब

कहा- 'ये 1954 से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग'

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने लिपुलेख दर्रा के मुद्दे पर नेपाल को करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों के संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब दिया। रणधीर जयसवाल ने कहा, 'इस संबंध में भारत का रुख हमेशा से एक जैसा और स्पष्ट रहा है। लिपुलेख दर्रा 1954 से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक पुराना मार्ग रहा है। इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। यह कोई नई बात नहीं है।'

मुद्दों पर बातचीत के लिए हमेशा तैयार

रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत, नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी मुद्दों पर रचनात्मक बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। इसमें बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सीमा से जुड़े उन लंबित मुद्दों को सुलझाना भी शामिल है, जिन पर दोनों पक्षों की सहमति है।'

जानिए क्या है पूरा मामला?

दरअसल, नेपाल ने रविवार को भारत और चीन द्वारा लिपुलेख दर्रे के रास्ते आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा आयोजित करने की योजना पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने दावा किया कि यह उसका क्षेत्र है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तीर्थयात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले काठमांडू से परामर्श नहीं किया गया। नई दिल्ली का यह निरंतर कहना रहा है कि कि लिपुलेख भारत का हिस्सा है।

जून और अगस्त में आयोजित है कैलाश मानसरोवर की यात्रा

नेपाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति उस वक्त जताई, जब भारत ने यह यात्रा जून और अगस्त के बीच आयोजित किए जाने की घोषणा की। नेपाल विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा, 'नेपाल सरकार अपने इस रुख पर पूरी तरह से कायम है कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी, 1816 की सुगौली संधि के आधार पर उसके अविभाज्य क्षेत्र हैं।' इसमें कहा गया है, 'नेपाल सरकार ने भारत और चीन दोनों के समक्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में अपना स्पष्ट रुख दोहराया है, जिसे नेपाली क्षेत्र लिपुलेख के रास्ते आयोजित किया जाना है।

आधार कार्ड के नए लुक को लेकर चल रही अफवाहों की क्या है हकीकत

PIB ने दूर किया भ्रम

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

आधार कार्ड के लुक में बदलाव को लेकर फैल रही अफवाहों का पीआईबी ने खंडन किया है। सरकारी प्रेस एजेंसी ने बताया है कि हाल ही में कुछ समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसी खबरें और पोस्ट प्रसारित हो रही हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि वर्ष के अंत तक आधार कार्ड के स्वरूप में बदलाव कर केवल एक फोटो और एक क्यूआर कोड तक सीमित किया जा सकता है। यह सही नहीं है। इस तरह के किसी भी बदलाव की कोई योजना नहीं है। पीआईबी ने कहा है कि इस तरह के समाचार और सोशल मीडिया पोस्ट लोगों के मन में अनावश्यक भ्रम पैदा कर रहे हैं। ऐसे में आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी खबरों और सोशल मीडिया पोस्टों को नजरअंदाज करें और यूआईडीएआई द्वारा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और पीआईबी के माध्यम से जारी प्रेस विज्ञप्तियों के द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करें।

सिर्फ छोटे बच्चों को आधार कार्ड जारी करने की अपील

अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि नए आधार कार्ड सिर्फ 6 साल तक के बच्चों के बनने चाहिए, ताकि घुसपैठियों के पास आधार कार्ड बनवाने का विकल्प न हो। इस याचिका पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ सोमवार को सुनवाई करेगी। याचिका में यह भी कहा गया है कि आधार कार्ड एक 'बुनियादी दस्तावेज' बन गया है।

बंगाल में जीत के बाद क्यों रो पड़े भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय?

आंखों से निकले आंसू

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाने जा रही है। बंगाल चुनाव के परिणाम के अनुसार भाजपा दो तिहाई से ज्यादा बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। हालांकि पश्चिम बंगाल की जीत की बात करते-करते कैलाश विजयवर्गीय भावुक हो गये और उनके आंखों से आंसू निकल गए और वह आंसू पोछते नजर आए। बता दें कि साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय केंद्रीय प्रभारी थे। उस चुनाव में भाजपा ने काफी मेहनत की थी, लेकिन भाजपा को मात्र 77 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था।

भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया

कैलाश विजयवर्गीय ने उस चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया था। मुझ पर और संघ के प्रचारकों पर केस किए गये। ऐसे केस किए गए जो नॉन बेलबेल थे। उन्होंने दावा किया कि नक्सलवाद को हटाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), और जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में BJP की जीत जितनी ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री शाह की रणनीति के जादू का नतीजा है। यह जीत मोदी और शाह की तरफ से देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के शासन में, पश्चिम बंगाल देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन रहा था।"

'झालमुरी' बना बंगाल में भाजपा की लोकप्रियता का प्रतीक

नेताओं ने एक-दूसरे के खिलाकर बांटी खुशियां

हिंदमाता नेटवर्क @ कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा में आया 'झालमुरी' 4 मई को नतीजों के दिन ट्रेंड कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एनडीए के नेता 'झालमुरी' खाकर बंगाल में पार्टी की बढ़त की खुशियां मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के झाड़ग्राम में सड़क किनारे रुकने और झालमुरी का आनंद लेने की व्यापक रूप से साझा की गई तस्वीर के बाद, चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में झालमुरी अप्रत्याशित रूप से चर्चा का विषय बन गया। यह दृश्य तुरंत वायरल हो गया और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगीं, जिनमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना भी शामिल है। बंगाली शब्द 'झाल' से व्युत्पन्न इस स्नैक के नाम का अर्थ मसालेदार या तीखा है, जो जल्द ही चुनाव प्रचार में एक प्रतीक बन गया। बाद में, एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इसमें राजनीतिक रंग भरते हुए कहा, मैंने झालमुरी खाई, लेकिन टीएमसी को असली झाल (मसाला) महसूस हुआ। मतगणना आगे बढ़ने के साथ, भाजपा ने अपनी मजबूत बढ़त बनाए रखी। भारतीय निर्वाचन आयोग के दोपहर 3:45 बजे के रुझानों के अनुसार, भाजपा 194 सीटों पर आगे थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस 89 सीटों पर आगे थी। भाजपा पहले ही तीन सीटें जीत चुकी थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस को केवल एक सीट मिली थी। पार्टी की मजबूत बढ़त को देखते हुए, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 'झाल' के प्रतीक को अपनाया और देश के विभिन्न हिस्सों में इस स्नैक के साथ जश्न मनाया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने झालमुरी खाते हुए अपनी तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जीत पर जलेबी काफी नहीं, सिर्फ झालमुरी ही काफी है। आज झालमुरी का दिन है, मैं इसे बड़े चाव से खा रहा हूं, इसलिए अगर किसी को इसमें तीखापन महसूस हो तो कृपया बुरा न मानें। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल की जीत पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह जीत आपके मार्गदर्शन और अमित शाह की बेमिसाल मेहनत का नतीजा है। बंगाल के हर एनडीए कार्यकर्ता को जीत की विशेष शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा का 'कमल' खिल उठा है। उन्होंने कहा कि देश के लोकप्रिय और प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने ममता दीदी को करारी हार का स्वाद चखाया है, विफलता की कड़वी 'झालमुरी'। गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से तंग आकर पश्चिम बंगाल की जनता ने सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना की है। उन्होंने विकास, प्रगति, स्थिरता और शांति के लिए अपना वोट डाला है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि में भाजपा की 'जीत' ऐतिहासिक थी। शिंदे ने तृणमूल कांग्रेस के गढ़ को 'नष्ट' करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के दशकों के अथक प्रयासों की भी सराहना की और उन्हें भाजपा का 'चाणक्य' बताया।

हिंदमाता एंकर तेज हवाओं के साथ उठती लहरों ने झील में स्थापित फ्लोटिंग हटमेंट को काफी नुकसान पहुंचाया और वह क्षतिग्रस्त होकर बहने लगे

टिहरी में टला बरगी डैम जैसा हादसा! डोबरा-चाटी झील में आंधी-तूफान के बीच SDRF ने बचाई 30 जिंदगियां

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

जबलपुर के बरगी डैम में स्टीमर डूबने की घटना के बाद एक और ऐसा हादसा टिहरी गढ़वाल की डोबरा-चाटी झील में एसडीआरएफ के साहसिक प्रयासों से टल गया। 02 मई 2026 को सायं लगभग 19:45 बजे डोबरा-चाटी झील क्षेत्र में अचानक आए भीषण आंधी-तूफान ने पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न कर दिया। तेज हवाओं के साथ उठती लहरों ने झील में स्थापित फ्लोटिंग हटमेंट को काफी नुकसान पहुंचाया और वह क्षतिग्रस्त होकर बहने लगे। इन हटमेंट्स में ठहरे पर्यटक अचानक आई इस आपदा के बीच घिर गए और मदद की गुहार लगाई।

पूरी तरह अलर्ट थी एसडीआरएफ की टीम

30 अप्रैल 2026 को जबलपुर के बरगी बांध क्षेत्र में हुई क्रूज़ दुर्घटना जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके मद्देनजर सेनानायकअर्पण यदुवंशी द्वारा पूर्व में ही टीमों को ब्रीफिंग तथा आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे, जिससे सभी टीमें पहले से ही पूर्ण तैयारी और सतर्कता की स्थिति में थीं। इसी सजगता के चलते स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांप लिया गया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के त्वरित कार्रवाई की गई।

सफल रेस्क्यू अभियान संचालित किया

कोटी कॉलोनी में स्थित SDRF टीम बिना देर किए SI नरेंद्र राणा के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। रात का समय, तेज आंधी, सीमित दृश्यता और झील की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच टीम ने अदम्य साहस, संयम और उच्च स्तर की पेशेवर दक्षता का परिचय दिया। घटनास्थल पर पहुंचते ही बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मौसम विभाग द्वारा पूर्व में जारी चेतावनियों के दृष्टिगत SDRF टीम पहले से ही संवेदनशील स्थलों पर अलर्ट मोड में तैनात थी। इसी सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया के कारण संभावित बड़ी दुर्घटना को घटित होने से रोका जा सका तथा समय रहते सफल रेस्क्यू अभियान संचालित किया गया।

एक–एक कर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला

SDRF टीम ने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में फ्लोटिंग हटमेंट तक पहुंच बनाते हुए एक–एक कर सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान टीम ने न केवल तकनीकी दक्षता बल्कि मानवीय संवेदनशीलता का भी परिचय दिया, जिससे घबराए हुए लोगों को भरोसा मिला। लगभग 25–30 व्यक्तियों को सुरक्षित निकालकर पर्यटन विभाग की बोट के माध्यम से सकुशल कोटी कॉलोनी पहुंचाया गया।

चारधाम यात्रा के पर्यटकों से अपील

इस त्वरित और साहसिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप एक संभावित बड़ी घटना को समय रहते टाल दिया गया। SDRF चारधाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं, नागरिकों एवं पर्यटकों से अपील करती है कि मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करें तथा खराब मौसम की स्थिति में जलाशयों एवं झील क्षेत्रों से दूर रहें। सतर्कता और जागरूकता ही किसी भी दुर्घटना से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है।

उत्तर प्रदेश में 38 IAS अफसरों का तबादला

8 जिलाधिकारी इधर से उधर

हिंदमाता नेटवर्क @ लखनऊ

यूपी में प्रशासनिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के तबादले करते हुए 38 अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल दी हैं। इस फेरबदल में कई जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं, जिससे जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देवरिया, जौनपुर, मऊ, महाराजगंज, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, संभल और प्रतापगढ़ जैसे अहम जिलों में नए डीएम तैनात किए गए हैं। शासन का मानना है कि इस बदलाव से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और जमीनी स्तर पर योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा।

पूरी ट्रांसफर लिस्ट

1. – मधुसूदन हुल्गी, विशेष सचिव, मुख्यमंत्री / अपर आवास आयुक्त को जिलाधिकारी, देवरिया बनाया गया है।
2. – सैमुअल पाल एन, प्रबंध निदेशक केस्को / अपर आयुक्त राज्य कर को जिलाधिकारी, जौनपुर बनाया गया है।
3. – अनंत वर्धन, उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण को जिलाधिकारी, मऊ की जिम्मेदारी मिली है।
4. –गौरव सिंह सोगरवाल, नगर आयुक्त गोरखपुर को जिलाधिकारी, महाराजगंज बनाया गया है।
5. – संतोष कुमार शर्मा, जिलाधिकारी महाराजगंज को जिलाधिकारी, फिरोजाबाद बनाया गया है।
6. – राजेंद्र पैंसिया, जिलाधिकारी संभल को जिलाधिकारी, मुरादाबाद बनाया गया है।
7. – अंकित खंडेलवाल, नगर आयुक्त आगरा को जिलाधिकारी, संभल बनाया गया है।
8. – अभिषेक पांडेय, अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त को जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ बनाया गया है।
9. – शिव सहाय अवस्थी, जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण बनाया गया है।
10. – अर्जुन सिंह, जिलाधिकारी बुलंदशहर को विशेष सचिव, मुख्यमंत्री बनाया गया है।
11. – अभिनव गोपाल, मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद को उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण बनाया गया है।
12. – अजय जैन, मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ को नगर आयुक्त, गोरखपुर बनाया गया है।
13. – डॉ। अलका वर्मा, निदेशक (प्रशासन) को विशेष सचिव, वित्त विभाग बनाया गया है।
14. – निधि बंसल, आईएफएस (प्रतिक्षारत) को निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं बनाया गया है।
15. – डॉ। दिनेश चंद्र, जिलाधिकारी जौनपुर को विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग बनाया गया है।
16. – प्रवीण मिश्रा, जिलाधिकारी मऊ को विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग बनाया गया है।
17. – रमेश रंजन, जिलाधिकारी फिरोजाबाद को अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त बनाया गया है।
18. – नेहा ब्याडवाल, संयुक्त मजिस्ट्रेट जालौन को मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई बनाया गया है।
19. – आलोक प्रसाद, संयुक्त मजिस्ट्रेट बहराइच को मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर बनाया गया है।
20. – कुमार सौरभ, संयुक्त मजिस्ट्रेट जौनपुर को मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद बनाया गया है।
21. – दयानंद प्रसाद, अपर मेला अधिकारी प्रयागराज को मुख्य विकास अधिकारी, गोंडा बनाया गया है।
22. – जुहेर बिन सगीर, विशेष सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को विशेष सचिव एनआरआई विभाग बनाया गया है।
23. – रिंकू सिंह राही को संयुक्त मजिस्ट्रेट, जालौन बनाया गया है।
24. – दिव्या मित्तल, जिलाधिकारी देवरिया को विशेष सचिव, राजस्व विभाग बनाया गया है।
25. – चंद्र शेखर, आईएफएस (प्रतिक्षारत) को विशेष सचिव, सिंचाई विभाग बनाया गया है।
26. – नेहा जैन को प्रबंध निदेशक, केस्को बनाया गया है।
27. – समीर को विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग बनाया गया है।
28. – सी। इंदुमती को निदेशक, महिला कल्याण बनाया गया है।
29. – डॉ। वंदना वर्मा को विशेष सचिव, गन्ना विकास विभाग बनाया गया है।
30. – संतोष वैश्य को नगर आयुक्त, आगरा बनाया गया है।
31. – राजेंद्र सिंह द्वितीय को सदस्य, राजस्व परिषद बनाया गया है।
32. – प्रेम प्रकाश सिंह को सदस्य, राजस्व परिषद बनाया गया है।
33. – अंकुर कौशिक को उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण बनाया गया है।
34. – अवनीश सक्सेना को विशेष सचिव, कार्मिक विभाग बनाया गया है।
35. – हरीकेश चौरसिया को सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाया गया है।
36. – मदन सिंह गब्र्याल को विशेष सचिव, आयुष विभाग बनाया गया है।
37. – सान्या छाबड़ा को अपर आयुक्त, राज्य कर बनाया गया है।

जिलों में नए डीएम की तैनाती

मधुसूदन हुल्गी को देवरिया का जिलाधिकारी बनाया गया है। सैमुअल पाल एन को जौनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। अनंत वर्धन को मऊ का डीएम बनाया गया है, जबकि गौरव सिंह सोगरवाल को महाराजगंज की कमान सौंपी गई है। संतोष कुमार शर्मा को फिरोजाबाद, राजेंद्र पैंसिया को मुरादाबाद और अंकित खंडेलवाल को संभल का जिलाधिकारी बनाया गया है। अभिषेक पांडेय को प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है।

विभागों में भी बड़ा फेरबदल

शिव सहाय अवस्थी को यूपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ। अलका वर्मा को वित्त विभाग में विशेष सचिव और रजिस्ट्रार फर्म-सोसायटी बनाया गया है। निधि बंसल को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में निदेशक (प्रशासन) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

रिंकू सिंह राही को मिली नई जिम्मेदारी

इस सूची में रिंकू सिंह राही का नाम खास चर्चा में रहा। उन्हें राजस्व परिषद से हटाकर जालौन में संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है। उन्होंने हाल में ही आईएएस से इस्तीफा यह कहते हुए दे दिया था कि उनके पास काम नहीं है, इसके कुछ दिनों बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया, अब उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है।

बंगाल में BJP की जबरदस्त जीत पर वाराणसी में बंटी झालमुड़ी

हिंदमाता नेटवर्क @ लखनऊ

पश्चिम बंगाल चुनाव मतगणना के नतीजे के रुझान भाजपा के पक्ष में आने से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की उत्साहित बंगीय समाज की महिलाओं ने गंगा घाट किनारे शंखनाद करके मां गंगा भोलेनाथ की प्रार्थना की और झालमुड़ी खाकर रुझान पर उत्साह दिखाया। साथ ही उम्मीद जताई कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीतने वाली है। यूं तो सुबह-ए-बनारस कचौड़ी जलेबी के नाश्ते के लिए मशहूर है लेकिन आज गंगा घाट के चौसट्टी घाट पर बंगाली समाज की महिलाओं ने झालमुरी से नाश्ता करके अपने दिन की शुरुआत की। बंगाली महिलाओं ने न केवल झालमुरी बनाया, बल्कि आपस में बांटकर खाया भी। इसके पहले बंगाली महिलाओं ने शंखनाद करके मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से कामना की कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय हो। बंगाली महिलाओं ने बताया कि जिस तरह से गरीबों का नाश्ता झालमुरी खाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में संदेश दिया। उसी को दोहराते हुए वह आज सुबह गंगा घाट किनारे न केवल झालमुरी का नाश्ता कर रही हैं, बल्कि उन्होंने शंखनाथ करके मां गंगा और भोलेनाथ से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय की भी प्रार्थना की है। बंगाल चुनाव में जैसे-जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में इसी तरह से उत्साह दिखाई पड़ रहा है। हालांकि, वोटों के गिनती पूरी होने के बाद ही राज्य में बहुमत को लेकर तस्वीर साफ हो सकेगी।

बाइक एक्सीडेंट के बाद मदद के लिए जमा हुई भीड़ को रेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर ने रौंदा

8 की मौत

हिंदमाता नेटवर्क @ बुलंदशहर

अंबेडकरनगर में मानवता दिखाने पहुंचे लोगों पर तेज रफ्तार कार काल बनकर टूटी। जलालपुर-अकबरपुर मार्ग पर घायल बाइक सवारों की मदद कर रहे ग्रामीणों को अनियंत्रित कार ने कुचल दिया। इस हादसे में कुल 8 लोगों की जान चली गई है, जिससे पूरे इलाके में मातम पसरा है।

अशरफपुर भुआ गांव के पास

यूपी के अंबेडकरनगर जिले के जलालपुर कोतवाली क्षेत्र में जलालपुर-अकबरपुर मार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना हुई। दो बाइकों की टक्कर में घायल हुए लोगों की मदद करने के लिए स्थानीय लोग मौके पर जमा हुए थे। तभी जलालपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने अनियंत्रित होकर भीड़ को रौंद दिया। हादसे में मौके पर और इलाज के दौरान कुल 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है।

मदद के दौरान बरपा काल

जलालपुर में अकबरपुर मार्ग पर स्थित अशरफपुर भुआ भट्ठे के पास पहले दो मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत हुई थी। इस भिड़ंत में दो लोग गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। आसपास के लोग तुरंत घायलों को अस्पताल भेजने और उनकी मदद करने के लिए सड़क पर इकट्ठा हुए। इसी मानवीय मदद के दौरान पीछे से आ रही कार ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया।

अस्पताल में तोड़ा दम

हादसे के बाद पुलिस ने घायलों को तत्काल सीएचसी नगपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं, दो अन्य गंभीर घायलों को पहले जिला अस्पताल और फिर टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हालांकि, इलाज के दौरान इन दोनों ने भी दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परिजनों की हर संभव सहायता के निर्देश दिए हैं।

नेशनल हाईवे-27 पर बिछी लाशें: अयोध्या से लौटते वक्त ट्रक से टकराई

6 की मौत, ड्राइवर को आ गई थी झपकी

हिंदमाता नेटवर्क @ बुलंदशहर

जालौन-झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे-27 पर सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कालपी कोतवाली क्षेत्र के जोल्हुपुर के पास चौरासी गुंबद के नजदीक हुआ, जहां तेज रफ्तार टवेरा कार पीछे से ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार चालक को झपकी आ जाने के कारण यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि टवेरा कार (नंबर CH 04 LT 5412) में सवार सभी लोग अयोध्या से दर्शन कर ललितपुर लौट रहे थे। जैसे ही वाहन जोल्हुपुर के पास पहुंचा, अचानक नियंत्रण बिगड़ने से कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी, जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे में मृतकों की पहचान ललितपुर जनपद के महरौनी थाना क्षेत्र के हरदौल मोहल्ला के रहने वाले लोगों के रूप में हुई।

शॉर्ट स्टोरी

विक्रमशिला पुल हादसे को लेकर एक्शन में CM सम्राट चौधरी, बुलाई उच्चस्तरीय बैठक

हिंदमाता नेटवर्क @ बगहा

बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने ऐतिहासिक विक्रमशिला ब्रिज पर रविवार रात बड़ा हादसा होते-होते टल गया। पुल का एक हिस्सा अचानक टूटकर नदी में गिर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि मौके पर मौजूद अधिकारियों ने पहले ही लोगों को पुल से हटा दिया था, जिसके कारण कोई जनहानि या घायल होने की खबर नहीं है। वहीं, घटना के बाद प्रशासन और सरकार तुरंत सक्रिय हो गई। पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से को लेकर सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर हालात का जायजा लिया जा रहा है और पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है। हादसे के बाद राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उच्चस्तरीय समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तत्काल उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई इस अहम बैठक में दोनों डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर पूरे मामले की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव सहित कई वरीय अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही विकास आयुक्त और पथ निर्माण विभाग के सचिव भी मौजूद रहे। पुल की स्थिति और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एनएचएआई के अधिकारियों को भी शामिल किया गया, ताकि तकनीकी पहलुओं पर तुरंत निर्णय लिया जा सके। सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यह पुल साल 2001 में लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था। करीब 4.5 किलोमीटर लंबा यह सेतु हजारों वाहनों और लाखों लोगों की रोजमर्रा की यात्रा का प्रमुख साधन था। लेकिन महज 25 साल के भीतर ही इसका एक बड़ा हिस्सा गंगा में समा गया, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत इस पर आवाजाही रोक दी।

प्रेमिका के लिए उजाड़ दिया घर: पति निकला पत्नी-बच्चों का कातिल!

हिंदमाता नेटवर्क @ मुजफ्फरपुर

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र से सामने आए दिल दहला देने वाले ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस हत्याकांड में किसी बाहरी दुश्मन का नहीं, बल्कि मृतका के अपने पति का ही हाथ निकला। घटना 28 अप्रैल 2026 की है, जब मधुबन जगदीश गांव में एक महिला और उसके दो मासूम बच्चों के शव संदिग्ध हालात में मिले थे। शुरुआत में मृतका के पति संतोष कुमार ने इसे जमीनी विवाद बताते हुए अपने ही रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की। जांच के दौरान जब तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल और एफएसएल रिपोर्ट खंगाली गई, तो कहानी पूरी तरह बदल गई। पुलिस को पति संतोष के बयानों में लगातार विरोधाभास मिला, जिससे शक गहराता गया। कड़ी पूछताछ के बाद संतोष कुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक, उसका अपनी कथित प्रेमिका करीना कुमारी के साथ लंबे समय से अवैध संबंध था। दोनों एक साथ रहना चाहते थे और इसी वजह से पत्नी और बच्चे उनके रास्ते की बाधा बन रहे थे। योजना के तहत संतोष ने पहले अपनी पत्नी को दवा देकर बेहोश किया, फिर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अपनी बेटी को भी गला दबाकर मार डाला और तीन महीने के मासूम बच्चे को मुंह दबाकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद संतोष ने पूरे मामले को जमीनी विवाद का रंग देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती और वैज्ञानिक जांच के आगे उसकी साजिश टिक नहीं सकी। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इस्तेमाल रस्सी और दवा भी बरामद कर ली गई है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के घर पर पुलिस रेड, जमीन कब्जाने से जुड़ा है मामला

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंगेर

बिहार के सिवान जिले में आज उस समय हड़कंप मच गया जब भारी पुलिस बल ने रघुनाथपुर के राजद विधायक ओसामा शहाब के आवासों पर एक साथ छापेमारी की। सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ओसामा के शहर स्थित 'नया किला' बंगले और उनके पैतृक गांव 'प्रतापपुर' पहुंची। तकरीबन आधा घंटे तक ओसामा साहब के नया किला के बंगला में छापेमारी चलती रही। उस वक्त ओसामा शहाब घर में मौजूद नहीं थे। उनकी मां हिना साहब घर में मौजद थी। हालांकि छापामारी उनके पैतृक गांव प्रतापपुर में भी जमकर की गई। वहां से भी कुछ भी नहीं प्रशासन को मिल सका। बता दें की कुछ दिनों पहले बड़हरिया रोड स्थित झुनापुर हाईवे के पास एक जमीनी विवाद में डॉक्टर सुधा सिंह ने महादेवा थाने में ओसामा साहब और उनके सहयोगी साबिर मियां और फरहान पर प्राथमिक दर्ज कराई थी। इसमें सीधे तौर पर ओसामा शहाब पर यह आरोप लगाया था कि जबरन मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं,जिसके बाद ओसामा साहब की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से खारिज हो गई ।अब मामला पटना उच्च न्यायालय में पहुंचा हुआ है। फिलहाल इस मामले में राजद के विधायक ओसामा साहब अभी फरार चल रहे हैं। जिस मामले में पुलिस ने आज उनके आवास पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि ओसामा शहाब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। शहाबुद्दीन अपने समय में सिवान में दबदबे और सियासी तूती के लिए मशहूर थे, लेकिन उनके निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत अब उनके बेटे ओसामा शहाब संभाल रहे हैं।

बीवी के 3 आशिक और खूनी बीयर पार्टी

बागपत में पति को रास्ते से हटाने के लिए जिगरी दोस्तों ने रची साजिश

हिंदमाता नेटवर्क @ बागपत

उत्तर प्रदेश के बागपत के शहर कोतवाली क्षेत्र के मितली गांव में 2 मई की सुबह फास्ट फूड विक्रेता मूलचंद उर्फ सोनू का शव एक ट्यूबवेल पर मिला था। अब खुलासा हुआ है कि मृतक के तीन दोस्तों विशाल, दीपक और रिंकू ने मूलचंद की पत्नी के साथ अपने अवैध संबंधों के चलते इस हत्या को अंजाम दिया। तीनों ने मूलचंद को घर से फोन कर ट्यूबवेल पर बुलाया और पहले साथ बैठकर शराब व बीयर पी। जैसे ही मूलचंद नशे में धुत्त हुआ, इन तीनों ने ईंट से उसका सिर कूचकर उसे मार डाला। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल ईंट बरामद कर ली है।

दोस्ती की आड़ में दगाबाजी

मृतक मूलचंद उर्फ सोनू गांव में ही फास्ट फूड की दुकान चलाता था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिन तीन दोस्तों- विशाल, दीपक और रिंकू- को वह अपना जिगरी यार समझता था, वे ही उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। इन तीनों का मूलचंद की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। मूलचंद को इस अवैध रिश्ते में कांटा मानते हुए तीनों ने उसे रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान तैयार किया।

शराब पार्टी और फिर मौत

साजिश के मुताबिक, आरोपियों ने मूलचंद को पार्टी के बहाने ट्यूबवेल पर बुलाया। वहां घंटों तक बीयर और शराब का दौर चला। जब मूलचंद पूरी तरह नशे की हालत में आ गया और अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं रहा, तब तीनों ने मिलकर पास पड़ी ईंट उठाई और उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। मौके पर बिखरी शराब की बोतलें और खून से सनी ईंटें इस बर्बरता की गवाह बनीं।

पुलिस का बड़ा खुलासा

घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सूरज राय के निर्देशन में टीम ने पड़ताल शुरू की। घटनास्थल के हालात और कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर पुलिस ने तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया। सख्ती से हुई पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एसपी ने बताया कि आरोपियों ने अवैध संबंधों की बाधा दूर करने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।

मरना तो नहीं चाहता, लेकिन पत्नी और सास ने...

ससुराल के गेट पर BJP नेता ने खाया जहर

हिंदमाता नेटवर्क @ फिरोजाबाद

दिल्ली के नरेला से भाजपा मंडल अध्यक्ष और बैंक फील्ड मैनेजर विनोद मिश्रा ने 1 मई को कानपुर में अपने ससुराल के गेट पर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मरने से पहले विनोद ने एक ऑडियो वायरल किया था, जिसमें उन्होंने पत्नी अनीता उर्फ आरती, सास और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। विनोद का कहना था कि ससुराल पक्ष उनकी पत्नी को विदा नहीं कर रहा था, जिससे तंग आकर वह जान दे रहे हैं। अब उनके बेटे कार्तिक ने बर्रा थाने में शिकायत दर्ज कराकर अपनी मां और ननिहाल वालों को पिता की मौत का जिम्मेदार ठहराया है।

मौत से पहले का दर्दनाक ऑडियो

विनोद मिश्रा ने जहर खाने से पहले 6-7 मिनट का एक ऑडियो रिकॉर्ड किया था। इस ऑडियो में उन्होंने रोते हुए कहा कि वह मरना नहीं चाहते, लेकिन पत्नी और ससुराल वालों ने उन्हें इस कदर मजबूर कर दिया है कि आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार भी लगाई थी। जहर खाने के बाद उनके दोस्त मनीष ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।

अंतिम विदाई में नहीं आई पत्नी

हैरानी की बात यह रही कि विनोद की मौत के बाद 2 तारीख को कन्नौज में उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उनकी पत्नी और ससुराल पक्ष का कोई भी सदस्य वहां नहीं पहुंचा। विनोद के भाई राजेश मिश्रा का दावा है कि उनके भाई ने ससुराल के अंदर ही जहर खाया है क्योंकि उन्हें वहां बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था।

बेटे ने मां पर लगाए आरोप

रविवार को विनोद का बेटा कार्तिक अपने चाचा के साथ थाने पहुंचा। कार्तिक का आरोप है कि उसकी मां अक्सर दिल्ली से घर के पैसे और जेवर लेकर कानपुर भाग आती थी। 2 अप्रैल को भी वह ऐसा ही करके दो बच्चों के साथ मायके आ गई थी। पिता उन्हें लेने कानपुर आए थे, लेकिन मां ने साथ जाने से इनकार कर दिया और ससुराल वालों ने उन्हें बेइज्जत किया। कार्तिक के मुताबिक, इसी अपमान के कारण उसके पिता ने जान दे दी।

हिंदमाता एंकर: आरोपी ने 14, 12, 10 और 8 वर्ष के चार बच्चों की ईंट और धारदार हथियार से हत्या की थी

कातिल मां नहीं, आमिर था! चार मासूमों और महिला की हत्या के बाद अब खुद एनकाउंटर में मारा गया

हिंदमाता नेटवर्क @ बरेली

अंबेडकरनगर जिले के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र मुरादाबाद मोहल्ले में 2 मई को चार सगे भाई-बहनों की हत्या के आरोपी आमिर को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। टांडा-बांदा हाइवे के किनारे पुलिस और स्वाट टीम के साथ हुई इस मुठभेड़ में आरोपी घायल हुआ था, जिसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी ने 14, 12, 10 और 8 वर्ष के चार बच्चों की ईंट और धारदार हथियार से हत्या की थी। बच्चों की मां का शव भी घर से 100 मीटर दूर नाले में मिला। वह भी इस सामूहिक हत्याकांड का शिकार हुई थी।

घर में बिछी थीं लाशें

अकबरपुर के मीरानपुर मुरादाबाद मोहल्ले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ही बिस्तर पर चार नाबालिग बच्चों के शव बरामद हुए। हत्यारे ने बच्चों के चेहरे पर ईंटों से वार किया था और गले को धारदार हथियार से रेता था। मृतकों में तीन लड़के और एक लड़की शामिल थे। घटना के वक्त बच्चों का पिता सऊदी अरब में था, जो पिछले चार वर्षों से घर नहीं लौटा है। शुरुआत में पुलिस बच्चों की मां को ही संदिग्ध मानकर तलाश कर रही थी।

नाले में मिला मां का शव

हत्याकांड के 24 घंटे के भीतर मामले में तब नया मोड़ आया जब गायब बताई जा रही मां का शव घटनास्थल से महज 100 मीटर दूर नाले के किनारे बरामद हुआ। मां का शव मिलने से पुलिस की थ्योरी पूरी तरह बदल गई। पहले पुलिस जिसे हत्यारोपी मान रही थी, वह खुद इस खौफनाक वारदात का शिकार निकली। एसपी प्राची सिंह के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज खंगालने और गहन छानबीन के बाद महिला का शव मिला, जिसकी पहचान उसके पति ने कीमां

मुठभेड़ में मारा गया अपराधी

पुलिस और स्वाट टीम ने मामले की संजीदगी को देखते हुए घेराबंदी शुरू की। ।स्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। आमिर का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है; वह पहले भी हत्या और दुराचार के मामले में जेल जा चुका था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। इस एनकाउंटर के साथ ही पांच हत्याओं के आरोपी का अंत हो गया।

पुलिस की कार्यशैली पर सवाल

इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की प्रारंभिक कार्यशैली पर भी सवाल उठे। पुलिस ने बिना पूरी जांच किए शुरुआत में ही मां को हत्यारोपी मान लिया था। हालांकि, नाले में महिला का शव मिलने के बाद जांच की दिशा बदली गई और असली आरोपी तक पहुंच सकी। इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

भारत के लिए राहत भरी खबर..

होर्मुज से सुरक्षित निकला एक और LPG टैंकर

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है और इस बार यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़ी है। दरअसल, यहां से गुजरते हुए एक और LPG टैंकर सुरक्षित तरीके से बाहर निकल चुका है और अब भारत की ओर बढ़ रहा है। खास बात यह है कि यह अकेला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई टैंकर इस रास्ते से भारत के लिए सफलतापूर्वक निकल चुके हैं, हालांकि कुछ जहाज अभी भी क्षेत्र में फंसे हुए हैं। ऐसे में यह ट्रांजिट भारत की सप्लाई के लिए राहत की तरह देखा जा रहा है। यह टैंकर मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला 'MT सर्व शक्ति' है, जिसमें करीब 46,313 टन LPG भरी हुई है। इसमें कुल 20 क्रू मेंबर हैं, जिनमें 18 भारतीय शामिल हैं। यह टैंकर 2 मई को होर्मुज पार कर चुका है और अनुमान है कि यह 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंच जाएगा।

होर्मुज की खाड़ी पार कर ओमान की खाड़ी में पहुंचा टैंकर

यह पूरा LPG कार्गो भारत की दैनिक ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इसे सप्लाई सिस्टम के लिए एक अहम राहत माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा रूट्स पर दबाव बना हुआ है। यह टैंकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) द्वारा चार्टर किया गया है। हालांकि यह मार्शल आइलैंड्स के झंडे के तहत चल रहा है, लेकिन इसका पूरा ऑपरेशन भारत की सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, जहाज फिलहाल ओमान की खाड़ी के आसपास है और भारत की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। यह ट्रांजिट इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि हाल के समय में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले भारत से जुड़े जहाजों की संख्या काफी कम हो गई थी। इसी बीच यह सुरक्षित निकलना एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि अभी भी करीब 14 भारतीय या भारत से जुड़े जहाज इस स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में किसी भी भारतीय जहाज के साथ कोई घटना सामने नहीं आई है। पोर्ट्स, शिपिंग और विदेश मंत्रालय मिलकर लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और क्रू की सुरक्षा व सप्लाई को सामान्य रखने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का कंट्रोल रूम भी दिन-रात एक किए हुए है। आप अंदाजा लगाइए कि अब तक लगभग 18 हजार ईमेल और 8 हजार से ज्यादा फोन कॉल अटेंड किए जा चुके हैं, ताकि हर जहाज की पल-पल की खबर रहे। इतना ही नहीं, सरकार ने अब तक करीब 3 हजार नाविकों को सुरक्षित उनके घर भी पहुंचाया है। राहत की बात यह भी है कि देश के किसी भी बंदरगाह पर फिलहाल कोई जाम नहीं है और सारा काम बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहा है।

राष्ट्रपति ने बालेन सरकार का अध्यादेश लौटाया

विपक्ष ने लगाए आरोप, नेपाल में सियासी घमासान

हिंदमाता नेटवर्क @ तेल अवीव

नेपाल की राजनीति में एक बार फिर संवैधानिक विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने प्रधानमंत्री बालेन शाह नेतृत्व वाली प्रचण्ड बहुमत की दो-तिहाई सरकार द्वारा भेजे गए संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश को मंजूरी देने से इनकार करते हुए पुनर्विचार के लिए सरकार को वापस लौटा दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, अध्यादेश में संवैधानिक परिषद की बैठक, गणपूरक संख्या (कोरम) और निर्णय प्रक्रिया से जुड़े प्रावधानों पर राष्ट्रपति ने गंभीर असहमति जताई है। राष्ट्रपति का कहना है कि संविधान में बहुमत आधारित निर्णय प्रणाली को किसी अध्यादेश या कानून के माध्यम से कमजोर नहीं किया जा सकता। सरकार ने दावा किया था कि संवैधानिक निकायों में नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, प्रभावकारी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह अध्यादेश लाया गया है। अध्यादेश में 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषद में सिर्फ सीमित सदस्यों की उपस्थिति में भी निर्णय लेने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। हालांकि राष्ट्रपति ने इसे संवैधानिक भावना के विपरीत माना। यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति और सरकार के बीच इस विषय पर टकराव हुआ हो। इससे पहले भी संवैधानिक परिषद संबंधी विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जा चुका था। उस समय भी राष्ट्रपति ने केवल प्रधानमंत्री और एक अन्य सदस्य की उपस्थिति में निर्णय लेने की व्यवस्था और संसदीय सुनवाई को कमजोर करने वाले प्रावधानों पर आपत्ति दर्ज कराई थी।

विपक्ष ने लगाए आरोप

वर्तमान अध्यादेश में सरकार ने कुछ संशोधन करते हुए अध्यक्ष सहित कम से कम चार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा था। साथ ही 3-3 मत विभाजन की स्थिति में प्रधानमंत्री के मत को निर्णायक मानने की व्यवस्था भी शामिल की गई थी। बावजूद इसके राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी नहीं दी। इस घटनाक्रम ने सरकार की कार्यशैली पर भी व्यापक राजनीतिक बहस छेड़ दी है। विपक्षी दलों और संवैधानिक विशेषज्ञों का आरोप है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार संसद को दरकिनार कर अध्यादेश के जरिए शासन चलाने की कोशिश कर रही है। विशेष रूप से आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि सरकार ने संसद का अधिवेशन बुलाने के मात्र 24 घंटे के भीतर उसे स्थगित कर दिया और उसके बाद लगातार आठ अध्यादेश जारी किए। विपक्ष इसे संसदीय प्रक्रिया और लोकतांत्रिक परंपराओं पर सीधा प्रहार बता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लौटाया जाना सरकार के लिए बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक झटका माना जा रहा है। अब सरकार के सामने या तो अध्यादेश में संशोधन कर दोबारा भेजने या फिर संसद के माध्यम से नया विधेयक लाने का विकल्प रहेगा। प्रधानमंत्री बालेन के द्वारा यह अध्यादेश संसद अधिवेशन को स्थगित कर लाए जाने से विपक्षी दल अपनी आपत्ति जता रहे हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने सरकार की सिफारिश पर नेपाल की संघीय संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन 30 अप्रैल 2026 के लिए बुलाया था। राष्ट्रपति पौडेल ने 22 अप्रैल को हुए मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 93(1) के तहत 30 अप्रैल 2026 को दोपहर 2 बजे संसद अधिवेशन बुलाया था, लेकिन 24 अप्रैल को बालेन की कैबिनेट ने राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन स्थगित करने की सिफारिश कर दी। संसद का सबसे महत्वपूर्ण माना जाने वाला बजट सत्र को स्थगित कर बालेन्द्र शाह की सरकार ने राष्ट्रपति के पास एक साथ आठ अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की। इनमें से राष्ट्रपति ने सात अध्यादेश तो जारी कर दिया पर एक अध्यादेश को नामंजूर करते हुए उसे सरकार को लौटा दिया है। विपक्षी दल सरकार पर संसद को दरकिनार कर अध्यादेशों के माध्यम से शासन चलाने का आरोप लगा रहे हैं।

ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, क्या अब मान जाएंगे ट्रंप?

हिंदमाता नेटवर्क @ वाशिंगटन

युद्ध खत्म करने के लिए ईरान ने अमेरिका को एक और प्रस्ताव भेजा है। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 पॉइंट का एक नया शांति प्रस्ताव भेजा गया है, जिसका मकसद युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना है। इसे अमेरिका के पिछले 9 पॉइंट के प्लान के जवाब में तैयार किया गया है। ट्रंप ने इस नए प्रस्ताव पर कहा कि वह इसपर विचार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पक्का नहीं पता कि वह ईरान के साथ कोई समझौता कर पाएंगे या नहीं। इससे पहले उन्होंने ईरान के एक पिछले प्रस्ताव पर निराशा जाहिर की थी। बता दें, 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता से युद्ध विराम शुरू हुआ, लेकिन अभी तक कोई शांति समझौता नहीं हो पाया है। ईरान चाहता है कि युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाए, जबकि ट्रंप की मांग है कि ईरान सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपनी प्रभावी नाकेबंदी खत्म करे। ट्रंप ईरान की परमाणु क्षमता को भी एक रेड लाइन (यानी ऐसी सीमा जिसे पार नहीं किया जा सकता) मानते हैं। वहीं ईरान साफ कर चुका है कि वह होर्मुज और यूरेनियम एनरिचमेंट पर अपने अधिकार से पीछे नहीं हटेगा।

अमेरिका नेवी ब्लॉकेड से फिर बिगड़े हालात

ईरान ने होर्मुज पर ब्लॉकेट 28 फरवरी कोअमेरिकी-इजराइली हमलों का जवाब में लगाया था। सीजफायर के बावजूद अमेरिका ने ईरानी पोर्ट्स पर नेवल नाकाबंदी जारी रखी है और दोनों पक्ष अभी भी होर्मुज स्ट्रेट में एक-दूसरे के जहाजों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें कब्जा कर रहे हैं और रोक रहे हैं। जिससे स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कभी भी युद्ध फिर से शुरू हो चुका है।

क्या है ईराम का 14 पॉइंट्स प्रस्ताव?

ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान का नया 14 पॉइंट प्रस्ताव अमेरिका समर्थित नौ पॉइंट्स प्लान का जवाब है, जिसमें मुख्य रूप से दो महीने के संघर्ष-विराम की मांग की गई थी। संघर्ष-विराम को आगे बढ़ाने के बजाय, ईरान चाहता है कि सभी मुद्दे 30 दिनों के भीतर सुलझा लिए जाएं और युद्ध का स्थायी खात्मा हो। मुख्य मांगों में भविष्य के हमलों के खिलाफ गारंटी, ईरान के आसपास से अमेरिकी सेना की वापसी, ईरान की जब्त संपत्तियों की रिहाई, प्रतिबंधों को हटाना, युद्ध-क्षतिपूर्ति, सभी युद्धों (लेबनान सहित) को खत्म करना और होर्मुज स्ट्रेट के कंट्रोल के लिए एक नई व्यवस्था शामिल है। ईरान NPT पर हस्ताक्षरकर्ता के तौर पर यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार पर भी जोर दे रहा है, हालांकि ट्रंप ने परमाणु मुद्दे को एक रेड लाइन बना दिया है। प्रस्ताव सौंपने के बाद ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि अब गेंद अमेरिका के पाले में है। जॉर्जटाउन के प्रोफेसर पॉल मस्कग्रे ने कहा कि ईरान ने अपने रुख में थोड़ी नरमी दिखाई है और संभवतः उसने यह पूर्व शर्त हटा दी है कि अमेरिका स्ट्रेट में ईरानी आवाजाही पर अपनी दूरस्थ नाकेबंदी समाप्त करे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि दो सबसे बड़े मुद्दों यूरेनियम एनरिचमेंट और हाई यूरेनियम एनरिचमेंट के हस्तांतरण पर अमेरिका और ईरान के बीच काफी मतभेद बने हुए हैं और ट्रंप इस बात पर अड़े हुए हैं कि ईरान अपनी परमाणु क्षमता पूरी तरह से त्याग दे।

क्या अमेरिका मानेगा ईरान का प्रस्ताव?

ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के प्रस्ताव को देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान बदसलूकी करता है, तो वाशिंगटन फिर से हमले शुरू कर सकता है। शनिवार को फ्लोरिडा में एयर फोर्स वन में चढ़ने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने साफ किया कि उन्हें समझौते की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी गई थी। राजनयिक पहल के बावजूद, राष्ट्रपति ने फिर से दुश्मनी शुरू होने की संभावना के बारे में अपने जाने-पहचाने बेबाक अंदाज में बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या हमले फिर से शुरू होंगे, तो ट्रंप ने कहा, "अगर वे कुछ बुरा करते हैं, तो इसकी संभावना है कि ऐसा हो सकता है।" ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका बहुत अच्छा कर रहा है और दावा किया कि ईरान समझौते के लिए बेताब है, क्योंकि महीनों के संघर्ष और नौसैनिक नाकेबंदी के कारण वह देश पूरी तरह तबाह हो चुका है।

पैगंबर की तरह खुद को देख रहे तालिबान के लीडर?

नाराज हुए अफगानी!

हिंदमाता नेटवर्क @ ब्रिटेन

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आने के बाद काफी हद तक शांति बनी हुई है और तालिबान तेजी से विकास के रास्ते पर चल रहा है। हालांकि, कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने मानव अधिकारों को लेकर कई चिंताएं जाहिर की हैं, जिन्हें तालिबान प्रशासन नजरअंदाज करता रहा है। अब तालिबान के अंदर ही फूट डलती दिखाई दे रही है और इसकी वजह तालिबान की टॉप लीडरशिप का अहंकार बन रहा है, जिसमें उन्हें अपने फैसले पर किसी की रोक-टोक बर्दाश्त नहीं है। तालिबान नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा ने हाल में एक बयान में अपने आदेशों को सभी के लिए जरूर मानने पर जोर दिया है।

बिजनेस वर्ल्ड

किचन में कम जल रहा गैस सिलेंडर! अप्रैल में LPG की खपत में 16% की कमी

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

जब से मिडिल ईस्ट में टेंशन शुरू हुई है और होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद किया गया है, उसके बाद घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई में काफी गिरावट देखने को मिली है। जिसकी वजह से देश के कई लोगों ने गैस सिलेंडर से शिफ्ट होकर पीएनजी और इंडक्शन पर आ गए हैं। जिसकी वजह से अप्रैल के महीने में देश में एलपीजी की खपत में भारी गिरावट देखने को मिली है। सरकारी की ओर से सोमवार को इसके आंकड़े भी जारी किए हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर एलपीजी की खपत में कितनी कमी आ गई है। सोमवार को जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने के कारण देश में रसोई गैस (एलपीजी) की खपत अप्रैल में 16 प्रतिशत से अधिक घटकर 22 लाख टन रह गई। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अप्रैल में एलपीजी की घरेलू खपत सालाना आधार पर 16.16 प्रतिशत घटकर 22 लाख टन रह गई जबकि अप्रैल 2025 में यह 26.2 लाख टन थी। मासिक आधार पर भी एलपीजी खपत में गिरावट दर्ज की गई है। मार्च 2026 में एलपीजी की घरेलू खपत 23.79 लाख टन रही थी। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आता है। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष छिड़ने के कारण इस मार्ग से आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से आने वाली गैस की खेपों में बाधा आई। सरकार ने घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए होटल और उद्योगों जैसे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति घटा दी है। साथ ही घरेलू सिलेंडर की दो रिफिलिंग के बीच अंतराल भी बढ़ाया गया है।

देश के सबसे अमीर सीएम बनेंगे थलपति विजय? दौलत जानकार रह जाएंगे हैरान

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

तमिलनाडु इतिहास रचने जा रहा है। कुछ समय पहले बनी साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय की पॉलिटिकल पार्टी टीवीके शुरुआती रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वैसे अभी तक तमिलनाडु में कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू सकी है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि एआईडीएमके और टीवीके मिलकर सरकार बना सकते हैं। जिसकी अगुवाई टीवीके के प्रमुख थलपति विजय कर सकते हैं। इसका मतलब है कि तमिलनाडु के अगले सीएम के रूप में थलपति विजय हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो थलपति विजय देश के सबसे अमीर सीएम के रूप में उभरकर सामने आ सकते हैं। ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं। थलपति विजय के इलेक्शन एफिडेविट को देखें तो उनके पास करीब 650 करोड़ रुपए की दौलत है। मौजूदा समय में देश में जितने भी सीएम है, उनके मुकाबले विजय थलपति के पास काफी ज्यादा दौलत है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर विजय थलपति के पास कितनी दौलत है और उन्होंने कहां कहां निवेश किया हुआ है। पेश से एक्टर और अब अपनी खुद की पार्टी खड़ी कर पॉलिटिकल लीडर बने विजय थलपति के पास काफी दौलत है। चुनाव आयोग को दिए इलेक्शन एफिडेविट के अनुसार विजय के पास 6,48,85,90,407 रुपए दौलत है। जिसमें 4,18,20,03,397 रुपए चल संपत्ति के तौर पर है। तो अचल संपत्ति के तौर पर 2,22,65,62,010 रुपए है। इस दौलत में उनकी पत्नी और डिपेंडेंट के पास कितनी दौलत है वो भी शामिल है। इलेक्शन एफिडेविट के अनुसार विजय की पत्नी के पास 15,57,29,421 रुपए की चल संपत्ति है। साथ ही दो डिपेंडेंट के पास क्रमशः 96,866 रुपए और 3,19,914 रुपए की चल संपत्ति है। इलेक्शन एफिडेविट में दी गई जानकारी के अनुसार विजय थलपति और उनके परिवार का काफी पैसा बैंकों में जमा है। आंकड़ों को देखें तो उनका और पत्नी और दो डिपेंडेंट के बैंक अकाउंट में 328 करोड़ रुपए से ज्यादा बैंकों में डिपॉजिट है। जबकि विजय ने बॉन्ड और शेयर में सिर्फ 19.37 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। अगर बात सोना और चांदी की बात करें तो थलपति विजय के पास 1.20 करोड़ रुपए का सोना 15 लाख रुपए की चांदी है। जबकि उनकी पत्नी के पास 2 किलो चांदी है जिसकी वैल्यू 4.75 लाख रुपए बताई गई है। साथ ही उनके पास 3132 ग्राम सोना है, जिसकी वैल्यू एफिडेविट में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई गई है।

सरकारी कंपनी BHEL का बड़ा धमाका, मुनाफा सीधे 3 गुना बढ़ा

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

शेयर बाजार में सरकारी कंपनियों का प्रदर्शन इन दिनों निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। इसी कड़ी में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने अपने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के नतीजों से बाजार में तहलका मचा दिया है। कंपनी के मुनाफे में ऐसी जबरदस्त उछाल आई है कि नतीजे घोषित होते ही भेल के शेयरों में निवेशकों की भारी खरीदारी देखने को मिली। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो यह खबर सीधे तौर पर आपके पोर्टफोलियो और बाजार की दिशा से जुड़ी है। भेल ने न सिर्फ अपनी कमाई के शानदार आंकड़े पेश किए हैं, बल्कि अपने शेयरधारकों को मुनाफे का सीधा हिस्सा बांटने का भी बड़ा ऐलान किया है। चौथी तिमाही (Q4FY26) के आंकड़े भेल और इसके निवेशकों के लिए किसी बड़े जश्न से कम नहीं हैं। कंपनी का एकीकृत शुद्ध मुनाफा (Consolidated Net Profit) सालाना आधार पर 155.82 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ 1,290.47 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। एक आम निवेशक के नजरिए से देखें तो, पिछले साल इसी तिमाही में यह आंकड़ा महज 504.45 करोड़ रुपये था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पिछली तिमाही (Q3FY26) से तुलना करें, तो यह उछाल और भी हैरान करने वाली है। पिछली तिमाही के 390.40 करोड़ रुपये के मुकाबले मुनाफे में 230 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। कमाई के मोर्चे पर भी भेल ने अपना दबदबा साबित किया है। कामकाज से होने वाला कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर करीब 37 फीसदी बढ़कर 12,310.3 करोड़ रुपये हो गया है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, तो कंपनी का कुल मुनाफा लगभग तीन गुना बढ़कर 1,600.26 करोड़ रुपये हो गया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 533.90 करोड़ रुपये था। कुल सालाना राजस्व भी 19 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 33,782.18 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। यह मजबूत बैलेंस शीट दिखाती है कि कंपनी का कारोबारी विस्तार तेजी से हो रहा है। जब कोई कंपनी भारी मुनाफा कमाती है, तो उसका सीधा फायदा उसके निवेशकों को भी मिलता है। भेल के बोर्ड ने इस शानदार वित्तीय प्रदर्शन के बाद अपने शेयरधारकों के लिए अंतिम डिविडेंड (Final Dividend) की सिफारिश की है। कंपनी 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 1.40 रुपये का डिविडेंड देगी। आसान वित्तीय भाषा में समझें तो यह चुकता पूंजी पर सीधे 70 प्रतिशत का पेआउट है। यह ऐलान उन निवेशकों के लिए एक बेहतरीन खबर है, जो शेयर की कीमत बढ़ने के साथ-साथ कंपनी से होने वाली नियमित आय (पैसिव इनकम) की उम्मीद रखते हैं।

बंगाल चुनाव नतीजों से इन शेयरों का दिखा दम, कोलकाता से है सबका कनेक्शन

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

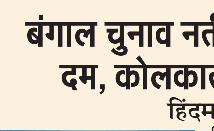

पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे एक तरह से सामने आ चुके हैं। प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने की कगार पर पहुंच चुकी है। ताजा आंकड़ों को देखें तो दोपहर 2 बजे के करीब टीएमसी 194 सीटों पर आगे चल रही है। इसका मतलब है कि शाम तक बीजेपी 200 के आंकड़े को भी छू सकती है। अगर ऐसा होता है कि करीब डेढ़ दशक के बाद बंगाल में सत्ता का परिवर्तन होगा। लेकिन अभी बात उन कंपनियों की करेंगे जो बंगाल से जुड़ी हुई हैं और शेयर बाजार में लिस्टेड है। ITC से लेकर ब्रिटानिया तक के शेयरों में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आईटीसी, इमामी, विशाल मेगामार्ट, गोयनका आदि कंपनियों के शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ कंपनियों के शेयरों में गिरावट भी देखी गई है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर बंगाल से जुड़ी कौन कौन सी कंपनियों के शेयरों में इजाफा देखने को मिल रहा है और किन शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। अगर बंगाल नतीजों की बात करें तो बीजेपी बड़ी जीत की ओर दिखाई दे रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी 194 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। जबकि तृणमूल कॉन्ग्रेस 95 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार बंगाल में दिखाई दे सकती है। जानकारों की मानें तो बीजेपी के सत्ता में आते देश की कई कॉरपोरेट कंपनियां बंगाल में अलग अलग सेक्टर में दिखाई दे सकती है। खासकर पोर्ट और एविएशन सेक्टर के अलावा ऑटो सेक्टर में निवेश देखने को मिल सकता है। वैसे ओवरऑल शेयर बाजार की बात करें तो सेंसेक्स दिन के पीक से करीब 700 प्वाइंट नीचे आ चका है। आंकड़ों को देखें तो दोपहर 3 बजकर 13 मिनट पर सेंसेक्स करीब 300 अंकों की तेजी के साथ 77,296.70 अंकों पर कारोबार कर रहा है। जबकि कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की तेजी देखने को मिली थी। वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी शेयर बाजार बंद होने से पहले 130 अंकों की तेजी के साथ कारोबार की रहा है और 24,132.05 अंकों पर दिखाई दे रहा है। जबकि कारोबारी सत्र के दौरान निफ्टी में 300 अंकोंका इजाफा देखने को मिला था।

युद्ध पर खुलकर आमने-सामने आए ईरान के मौलवी

कट्टरपंथी और उदारवादी आपस में भिड़ें

हिंदमाता नेटवर्क @ बुलंदशहर

अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध ने ईरान के धार्मिक नेतृत्व (क्लर्जी) के भीतर खुलकर मतभेद सामने आए हैं। एक तरफ कट्टरपंथी नेता युद्ध को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उदारवादी आवाजें लगातार लड़ाई के भारी नुकसान को देखते हुए बातचीत का रास्ता अपनाने की सलाह दे रहे हैं। हाल के हफ्तों में दोनों पक्षों के बीच संकट कम करने के प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन वॉशिंगटन और तेहरान के बीच अभी भी बड़ी असहमति बनी हुई है। ईरान इंटरनेशनल की खबर के मुताबिक कट्टरपंथी मौलवी और सांसद महमूद नबावियन ने साफ किया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो ईरान बड़ा और कठोर जवाब देगा। उन्होंने कहा कि ईरान अरब देशों के उन इलाकों को निशाना बनाएगा, जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे और ठिकाने हैं।

उदारवादी लोग कर रहे बातचीत के रास्ते की वकालत

इसके बिल्कुल उलट उदारवादी मौलवी और मानवाधिकार वकील मोहसिन रोहामी ने चेतावनी दी है कि लंबे युद्ध से ईरान को जो नुकसान हुआ है, उसे सालों में ठीक नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि स्टील फैक्ट्रियां, रिफाइनरी, बिजली और गैस के बड़े ढांचे तबाह हो गए हैं। रोहामी ने कहा कि जो लोग अमेरिका से बातचीत का विरोध कर रहे हैं, उन्हें युद्ध में हुई जान-माल की तबाही के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उनका कहना है कि 'शांति सामान्य स्थिति है और युद्ध अपवाद'। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की सड़कों पर लोग बातचीत का विरोध नहीं कर रहे हैं और यह जनता की मांग के साथ-साथ रणनीति की जरूरत भी है।

कट्टरपंथियों की वजह से ईरान कर रहा बड़ी भूल

ईरान की वेबसाइट 'अस्र ईरान' पर छपे एक विश्लेषण में कट्टरपंथियों की चार बड़ी रणनीतिक भूलें गिनाई गई हैं। इसमें कहा गया है कि उन्होंने अमेरिका और इजराइल की ताकत को कम आंका और सिर्फ दुश्मन के नुकसान पर ध्यान दिया, जबकि ईरान के अपने खर्चों को नजरअंदाज कर दिया।

कनाडा की नई खुफिया रिपोर्ट खालिस्तान चरमपंथियों को माना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

हिंदमाता नेटवर्क @ इस्लामाबाद

खालिस्तानी चरमपंथियों के लिए अब कनाडा सुरक्षित स्थान नहीं रहा है। कनाडा के एजेंसियों भी खालिस्तानियों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा मान रही हैं। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने खालिस्तानी चरमपंथियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। एजेंसी ने कहा कि यह समूह अपने हिंसक चरमपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए देश की संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करता है। अपनी 2025 की पब्लिक रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा कि कनाडा में मौजूद खालिस्तानी चरमपंथियों (CBKE) की गतिविधियां कनाडा और उसके हितों के लिए लगातार एक गंभीर खतरा बनी हुई हैं, खासकर हिंसक गतिविधियों में उनके शामिल होने को लेकर।

खालिस्तानी चरमपंथी भारत में करते हैं एक अलग राष्ट्र की मांग

खालिस्तानी चरमपंथी समूह भारत के भीतर एक संप्रभु राज्य बनाने की मांग करते हैं। अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण नई दिल्ली ने इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। यह रिपोर्ट एयर इंडिया की फ्लाइट 182 पर हुए बम धमाके की 40वीं बरसी के एक साल बाद आई है। इस धमाके के संदिग्ध CBKE समूहों के सदस्य थे। रिपोर्ट में कहा गया है, "आज भी यह कनाडा के इतिहास का सबसे घातक आतंकवादी हमला माना जाता है, जिसमें 329 लोग मारे गए थे, इनमें से ज़्यादातर लोग कनाडा के ही नागरिक थे।

नई रिपोर्ट में खालिस्तान को बताया देश के लिए खतरा

शुक्रवार को कनाडा सरकार की वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट में कहा गया, "कुछ CBKEs के कनाडा के नागरिकों से अच्छे संबंध हैं। ये लोग कनाडा की संस्थाओं का इस्तेमाल अपने हिंसक चरमपंथी एजेंडे को बढ़ावा देने और समुदाय के ऐसे सदस्यों से चंदा इकट्ठा करने के लिए करते हैं जिन्हें इसकी भनक भी नहीं होती। बाद में इस पैसे का इस्तेमाल हिंसक गतिविधियों के लिए किया जाता है।"

भारत-कनाडा रिश्ते

2023 में भारत और कनाडा के संबंधों में तब भारी गिरावट आई, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की धरती पर सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया। नई दिल्ली ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। पिछले साल मार्क कार्नी के पदभार संभालने के बाद से, दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने और फिर से मज़बूत बनाने के प्रयास कर रहे हैं।

हिंदमाता एंकर 000

मध्यस्थ बनकर पाकिस्तान ने कर लिया अपना धंधा सेट, ईरान के माल से कर

हिंदमाता नेटवर्क @ वाशिंगटन

होर्मुज के बाहर अमेरिकी नेवी ने ब्लॉकेड लगा दिया है, साथ ही युद्ध के बाद ईरान के UAE के साथ रिश्ते बेहद खराब हो गए हैं। युद्ध से पहले अपने व्यापार के लिए ईरान UAE की पोर्ट्स का भी इस्तेमाल करता था। अमेरिकी ब्लॉकेड और UAE से खराब रिश्तों ने ईरान के व्यापार को गहरी चोट दी है, लेकिन ईरान ने इनका हल निकालते हुए पाकिस्तान के साथ अपना पुराना समझौता एक्टिव कर दिया है। ईरान और पाकिस्तान के इस समझौते से पाकिस्तान को भी बड़ा फायदा हो रहा है। तसनीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अपने इलाके और बंदरगाहों के जरिए ईरान में सामान के ट्रांजिट को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कराची, पोर्ट कासिम और ग्वादर ईरान के व्यापार के लिए अहम लॉजिस्टिक गेटवे बन गए हैं, जबकि दूसरी ओर वाशिंगटन की समुद्री नाकेबंदी ईरान की वैश्विक व्यापार तक पहुंच को रोकने की कोशिश कर रही है। यह कदम एक अहम बदलाव का संकेत है, क्योंकि ईरान लंबे समय से क्षेत्रीय व्यापार तक पहुंच के लिए UAE के बंदरगाहों, खास तौर पर जेबेल अली पर निर्भर रहा था।

ईरान पाकिस्तान के रास्ते बेच रहा अपना माल

इस्लामाबाद के कॉमर्स मंत्रालय ने 25 अप्रैल को पाकिस्तान के इलाके से सामान के ट्रांजिट का आदेश 2026 जारी किया, जिसे तुरंत लागू कर दिया गया है। यह आदेश 2008 में तेहरान के साथ हुए एक द्विपक्षीय सड़क परिवहन समझौते को सक्रिय करता है, जिसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया था। इस आदेश के तहत छह जमीनी रास्ते खोले गए हैं, जो पाकिस्तान के तीन मुख्य बंदरगाहों को बलूचिस्तान के रास्ते ईरान की दो सीमा चौकियों, गब्द और ताफ्तान से जोड़ते हैं। यह ऐलान उसी समय हुआ है, जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद के दौरे पर थे।

पाकिस्तान का हो गया धंधा सेट

पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक ग्वादर-गब्द कॉरिडोर, जो इन तय रास्तों में सबसे छोटा है। ईरान की सीमा तक पहुंचने में लगने वाले समय को घटाकर दो से तीन घंटे कर देता है। साथ ही, कराची के रास्ते माल भेजने की तुलना में इस रास्ते से परिवहन लागत में 45 से 55 फीसद तक की कमी आने का अनुमान है। साथ ही जब ईरान का माल यहां से जा रहा है तो पाकिस्तान को भी खूब फायदा हो रहा है। पाकिस्तान के बंदरगाह अब एक बड़ा व्यापार आवाजाही हब बन रहे हैं। कराची और पोर्ट कासिम मिलकर हर साल लगभग 42 मिलियन टन कार्गो संभालते हैं, और इनमें काफी ज़्यादा अतिरिक्त कार्गो संभालने की गुंजाइश भी है। इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक जब से युद्ध शुरू हुआ है, पाकिस्तान की ओर मोड़े गए कार्गो का लगभग 75 फीसद हिस्सा अकेले कराची ने ही संभाला है। ग्वादर बंदरगाह जिसे 'चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी' द्वारा 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' (CPEC) के मुख्य केंद्र के तौर पर संचालित किया जाता है, ईरान के चाबहार बंदरगाह से लगभग 170 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस तरह इन तीनों बंदरगाहों में से यह भौगोलिक रूप से ईरानी क्षेत्र के सबसे करीब है।

दैनिक ठाणे, मंगलवार 5 मई, 2026

हिंदमाता मिरर

पैनी नजर, पुख्ता खबर

तृषा कृष्णन की सगाई टूटी

साउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस तृषा कृष्णन 4 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। तृषा साउथ के साथ-साथ बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जलवा दिखा चुकी हैं। हालांकि तृषा फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इनमें सगाई टूटने, प्राइवेट फोटो लीक होने और शादीशुदा मर्दों संग नाम जुड़ने के किस्से शामिल है। तृषा का नाम वैसे तो कई एक्टर्स संग जुड़ चुका हैं लेकिन वह 43 साल की उम्र में भी कुंआरी हैं। तृषा कृष्णन का नाम सबसे पहले सुपरस्टार थलापति विजय के साथ जुड़ा था। दोनों के कथित अफेयर की खबरों ने साल 2005 में खूब सुर्खियां बटोरी थी। तृषा के साथ बढ़ती नजदीकियों के कारण विजय की मैरिड लाइफ मुश्किल में पड़ गई थी। हालांकि, दोनों ने कभी अपना रिश्ता कबूल नहीं किया।

■ इसके बाद तृषा कृष्णन का नाम बाहुबली फेम राणा दग्गुबाती के साथ जुड़ा। तृषा और राणा दग्गुबाती की कुछ इंटीमेंट तस्वीरें भी लीक हुई थीं। राणा दग्गुबाती ने करण जौहर के चैट में तृषा कृष्णन के साथ रिलेशनशिप में होने की बात भी स्वीकारी थी। साउथ सुपरस्टार धनुष के साथ भी तृषा का नाम जुड़ चुका है। दिसंबर 2015 में तृषा ने बिजनेसमैन वरुण मनियन के साथ अपनी सगाई का ऐलान भी किया था। बताया जाता है कि धनुष की वजह से तृषा की सगाई भी टूट गई थी। तृषा और धनुष की बेड से एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।

■ तृषा ने फाल्गुनी पाठक के गाने 'मेरी चुनर उड़ी उड़ी जाए' से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद प्रियदर्शन ने उन्हें अपनी फिल्म 'लेसा लेसा' में काम करने का ऑफर दिया था। तृषा 2002 में रिलीज फिल्म 'मौनम पेसीयाडे' में बतौर लीड एक्ट्रेस पहली बार नजर आई थीं। तृषा कृष्णन इन दिनों थलपति विजय संग अफेयर को लेकर छाई हुई है। हाल ही में विजय ने अपनी पत्नी से तलाक लेने की घोषणा की है। इसके बाद से तृषा और विजय की नजदीकियों को फिर हवा मिल गई है। दोनों करीब 5 फिल्मों में साथ नजर आए हैं, जिनमें से 2023 में रिलीज सुपरहिट फिल्म लियो भी शामिल है।

राधा का टी-20 विश्वकप में चयन से बल्ले और गेंद से सुधार : तनुजा कंवर

- 9 मैचों में 114 रन बनाए।
- 66 रन की एक पारी भी शामिल।
- 2 विकेट मिले।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बाएं हाथ की स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर तनुजा कंवर ने कहा है कि राधा यादव का 2026 महिला टी-20 वर्ल्ड कप टीम में चयन एक बड़ा कमबैक है। उन्होंने बताया कि राधा को टीम में जगह उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में हुए बड़े सुधार की वजह से मिली है।

■ राधा यादव ने आखिरी बार 2025 में इंग्लैंड दौरे पर टी-20 मैच खेला था, जहां उन्होंने छह विकेट लिए थे और भारत ने दोनों व्हाइट बॉल सीरीज जीती थीं। इसके बाद उन्हें 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में भी शामिल किया गया। लेकिन टीम में कई बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज होने के कारण उन्हें श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज में मौका नहीं मिला। इसके बाद राधा ने महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए शानदार प्रदर्शन किया। टीम के दूसरी बार खिताब जीतने में उनका योगदान रहा। उन्होंने 9 मैचों में 114 रन बनाए, जिसमें 66 रन की एक पारी भी शामिल थी, हालांकि उन्हें सिर्फ 2 विकेट मिले।

■ राधा ने भारत 'ए' टीम की कप्तानी करते हुए बैंकॉक में महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट भी जिताया। इस दौरान उन्होंने 75 रन बनाए और गेंदबाजी में 5 रन प्रति ओवर की दर से 10 विकेट लिए। सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी में वेस्ट जोन टीम उपविजेता रही, जिसमें राधा ने चार पारियों में 224 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 108 रन रहा और उन्होंने 12 विकेट भी लिए। इस प्रदर्शन के दम पर वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में दूसरे स्थान पर रहीं।

■ सीम गेंदबाजी ऑलराउंडर अमनजोत कौर (पीठ की चोट) और कशवी गौतम (घुटने की चोट) के चोटिल होने के साथ-साथ राधा के अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें फिर से टी-20 वर्ल्ड कप टीम और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की सीरीज में जगह दिलाई।

■ तनुजा कंवर ने एक इवेंट के दौरान आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि मुझे लगता है यह बहुत अच्छा है कि राधा का चयन टी-20 वर्ल्ड कप के लिए हुआ। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में काफी सुधार हुआ है, इसलिए यह एक बड़ा कमबैक है। मुझे लगता है कि राइजिंग स्टार्स एशिया कप में उनकी कप्तानी भी बहुत अच्छी रही। उन्होंने मुश्किल हालात को बहुत अच्छे तरीके से संभाला।

■ अब तनुजा का ध्यान भारत 'ए' टीम के इंग्लैंड दौरे की तैयारी पर है। इस दौरे में 20 जून से 4 जुलाई तक तीन वनडे और तीन टी-20 मैच खेले जाएंगे। टी-20 मैच नॉर्थहैम्पटन और चेल्म्सफोर्ड में 20 से 25 जून के बीच होंगे, जबकि वनडे मैच 28 जून से 4 जुलाई के बीच होव और टॉनटन में खेले जाएंगे।

■ तनुजा ने कहा कि बीसीसीआई द्वारा 'शैडो टूर' बढ़ाने से खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए बेहतर तैयारी का मौका मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पहले भारत 'ए' महिला टीम को ज्यादा मैच नहीं मिलते थे, लेकिन अब लगातार मैच हो रहे हैं, जो खिलाड़ियों के लिए बहुत फायदेमंद है। भारत 'ए' टीम में खेलने से हमें बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने और मजबूत टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है। इससे खिलाड़ियों में परिपक्वता आती है और वे भारतीय टीम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं।

■ उन्होंने आगे कहा कि हम पहली बार इंग्लैंड में खेलने जा रहे हैं। वहां की परिस्थितियां हमारे लिए नई होंगी। यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर होगा, लेकिन हम इसके लिए अच्छी तैयारी करेंगे। इस साल की शुरुआत में बैंकॉक में इंडिया 'ए' के 'राइजिंग स्टार्स महिला एशिया कप' जीतने के बारे में बात करते हुए तनुजा ने उस मानसिक मजबूती के बारे में बताया जो टीम ने अपने पहले मैच में यूएई से अप्रत्याशित हार के बाद दिखाई थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा एहसास था। हम इससे पहले 'इमर्जिंग एशिया कप' में चैंपियन रह चुके थे। लेकिन जब हम पहला मैच हारे, तो हम थोड़े निराश थे कि हम एक बहुत अच्छी टीम थे और हम एक मैच हार गए, लेकिन हमें बताया गया कि क्रिकेट में यह कोई बड़ी बात नहीं है। किसी दिन आप किसी टीम से हार सकते हैं, लेकिन हम हार के बाद कैसे वापसी करते हैं, यह बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हमने वापसी करने के मामले में भी वही तरीका अपनाया और इसीलिए हमें ट्रॉफी मिली।

■ विमेंस प्रीमियर लीग की बल्लेबाजों के लिए मददगार पिचों से बैंकॉक की धीमी पिचों पर ढलना टीम के लिए एक बड़ी चुनौती थी। तनुजा ने इस टूर्नामेंट में नौ विकेट लिए और उनके लिए सफलता की कुंजी अपनी गेंद की लेंथ को सही करना था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पिचें बहुत धीमी थीं, इसलिए हमें उसके हिसाब से खेलना पड़ा। हम विमेंस प्रीमियर लीग से आए थे, जहां पिचें बहुत अच्छी थीं। इसलिए, हालात को समझने और उनके हिसाब से ढलने में हमें थोड़ा समय लगा। लेकिन बाद में हमने हालात के हिसाब से खुद को सही तरीके से ढाला। तो यह एक बहुत बड़ी बात थी।'

कान 2026 में एक बार फिर चमकेंगी जैकलीन फर्नांडिस

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिससे उनकी ग्लोबल पहचान और मजबूत हो रही है। पिछले कुछ सालों से वो इस बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल का जाना-माना चेहरा बनी हुई हैं और एक बार फिर वो सिनेमा और फैशन की दुनिया के सबसे बड़े मंचों में से एक पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। 79वां एनुअल कान फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में 12 से 23 मई 2026 तक होने वाला है और जैकलीन की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। फैशन फिटिंग्स से लेकर कपड़े फाइनल करने तक, जैकलीन अभी रेड कार्पेट के लिए अपने लुक्स तैयार करने में लगी हुई हैं।

■ जैकलीन के काम से जुड़े एक करीबी सूत्र का कहना है कि कान में जैकलीन का आना हमेशा उनकी ग्लोबल पर्सनालिटी को दिखाता है। हर साल, वो ये पक्का करती हैं कि उनकी मौजूदगी सिर्फ फैशन और ग्लैमर तक ही सीमित न रहे, बल्कि वो पूरी ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट करें। इस साल भी, वो अपने ग्लोबल इमेज के हिसाब से अलग-अलग लुक्स फाइनल कर रही हैं और अपनी जड़ों को भी सेलिब्रेट कर रही हैं।

■ पिछले कुछ सालों में जैकलीन का कान फिल्म फेस्टिवल के साथ एक मजबूत नाता बन गया है और उन्होंने कई बार वहां आकर इंटरनेशनल लेवल पर खूब चर्चा बटोरी है। 2025 में उन्हें 'रेड सी फिल्म फाउंडेशन' की 'वीमेन इन सिनेमा' पहल से सम्मानित किया गया था, जहां उन्हें सिनेमा में उनके योगदान के लिए 6 ग्लोबल महिलाओं में गिना गया था। इस सम्मान ने यह दिखाया कि उनका असर सिर्फ मेनस्ट्रीम एंटरटेनमेंट से कहीं आगे बढ़ रहा है और ग्लोबल कल्चरल चर्चाओं में उनकी अहमियत बढ़ रही है।

■ इससे पहले, जैकलीन ने 2024 में कान अटेंड किया था, जहां उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और 'द सब्सटेंस' के प्रीमियर में शामिल हुईं। अपने रेड कार्पेट अपीयरेंस और ग्लोबल फैशन चॉइसेस के लिए उन्होंने खूब चर्चा बटोरी। अब एक और बार कान जाने की तैयारी के साथ, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस साल जैकलीन उस शानदार रेड कार्पेट पर क्या नया लेकर आती हैं।

श्वेता तिवारी का गोल्डन लुक

टेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है। हाल ही में श्वेता तिवारी ने गोल्डन कलर की साड़ी में अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है। साड़ी के साथ श्वेता ने डार्क ग्रीन कलर का ब्लाउज कैरी किया है।

■ ब्लाउज की डीप नेकलाइन और उस पर की गई फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी श्वेता के इस लुक को बहुत ही बोल्ड और आकर्षक बना रही है। गोल्डन और ग्रीन का यह कॉन्ट्रास्ट बेहद रॉयल और क्लासी लग रहा है। इस एथनिक लुक को और भी खास बनाने के लिए, श्वेता ने बहुत ही पारंपरिक और भारी ज्वेलरी चुनी है। उन्होंने कानों में खूबसूरत झुमके, गले में सोने का एंटीक हार और हाथों में मैचिंग कंगन पहने हैं।

■ इसके साथ ही, उनका खुला हेयरस्टाइल और माथे की छोटी सी बिंदी उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। श्वेता का मेकअप सटल और ग्लोइंग है, जो उनके पूरे लुक को बैलेंस्ड बना रहा है। तस्वीरों में श्वेता तिवारी के चेहरे की हल्की मुस्कान और उनके कातिलाना पोज फैंस का ध्यान खींच रहे हैं। वे कभी अपने बालों को संवारती हैं, तो कभी मुस्कुराते हुए जमीन की ओर देखती नजर आ रही हैं।

राम चरण स्टारर पेड्डी में स्पेशल सॉन्ग के लिए शामिल हुईं श्रुति

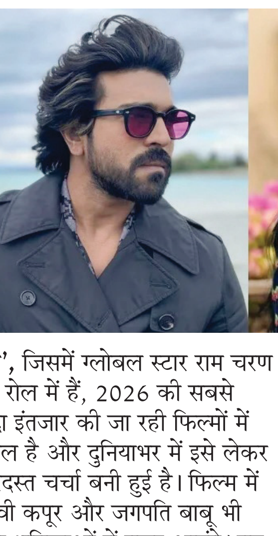

'पेड्डी', जिसमें ग्लोबल स्टार राम चरण लीड रोल में हैं, 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में शामिल है और दुनियाभर में इसे लेकर जबरदस्त चर्चा बनी हुई है। फिल्म में जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म का म्यूजिक पहले ही माहौल बना चुका है, चार्टबस्टर हिट्स दे चुका है और एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। अब इस फिल्म को लेकर और बड़ा अपडेट सामने आया है। पैन-इंडिया सिनेमा की बज गर्ल श्रुति हासन फिल्म में एक हाई-एनर्जी स्पेशल डांस नंबर में नजर आने वाली हैं, जिसकी शूटिंग इस वक्त चल रही है। इससे पहले श्रुति को एक और बड़े प्रोजेक्ट वाराणसी के लिए भी अप्रोच किया गया था। इससे साफ है कि भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी आने वाली फिल्मों में उनकी डिमांड और मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। पेड्डी का म्यूजिक एल्बम तेजी से बड़ा चर्चा का विषय बनता जा रहा है।

'धूम 4' का हिस्सा बनेगी उर्वशी?

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला हाल ही में अचानक सुर्खियों के केंद्र में आ गई हैं, क्योंकि उनका नाम बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धूम 4' से जुड़ी चर्चाओं में सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। हालांकि फिल्म निर्माताओं की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

■ लेकिन ऑनलाइन चर्चाओं से यह साफ है कि दर्शक उर्वशी को इस हाई-ऑक्टेन फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनते देखने के लिए उत्साहित हैं—संभवत: रणबीर कपूर के साथ, जिनके फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने की अफवाहें पहले से ही जोरों पर हैं, और यह फिल्म आदित्य चोपड़ा के बैनर तले बन सकती है। इस उत्साह की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से फैंस के बीच से ही उभरा है। फैन एडिट्स, कास्टिंग पोल्स और चर्चाओं की बाढ़ सी आ गई है, जिसमें उर्वशी रौटेला को एक ग्लैमरस और एक्शन से भरपूर भूमिका के लिए एक अनोखे लेकिन लोकप्रिय विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

■ उर्वशी की प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस और आत्मविश्वास भरे अंदाज को देखते हुए कई लोग मानते हैं कि वह धूम यूनिवर्स में एक नई ऊर्जा ला सकती हैं, जो हमेशा से स्टाइल, स्पेक्टेकल और विजुअल अपील के लिए जाना जाता है। यह चर्चा इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यह दर्शकों की बदलती सोच को दर्शाती है। आज के फैंस सिर्फ घोषणा का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद बातचीत की दिशा तय करते हैं। उर्वशी की ग्लोबल अपील, फैशन-फॉरवर्ड इमेज और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती पहचान ने उन्हें दर्शकों के बीच एक मजबूत दावेदार बना दिया है।

मलाइका फिर खो बैठीं हैं अपना दिल

अक्सर अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी लव लाइफ की वजह से काफी सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में फिर से कुछ ऐसा हुआ है कि सबका ध्यान फिर से मलाइका की तरफ चला गया है। बीते दिनों अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप को लेकर मलाइका काफी चर्चा में थी और अब अर्जुन से ब्रेकअप के बाद वो फिर से सुर्खियों में आ गईं। हाल ही में मलाइका की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो एक मिस्ट्री मैन का हाथ थामे नजर आ रही हैं। इस वीडियो में एक व्यक्ति जिसकी अब तक पहचान नहीं हुई है वो मलाइका का हाथ पकड़ कर उन्हें भीड़ से बचाता हुआ बाहर लेकर जा रहा है। इस वीडियो के बाद से ही उनके फैंस ये जानने के लिए काफी उत्सुक हैं कि क्या मलाइका फिर से किसी के प्यार में हैं ?

ऐसी है मलाइका की लव लाइफ

मलाइका की लव लाइफ किसी बॉलीवुड स्टोरी से कम नहीं है। अरबाज खान से शादी करने के बाद उनका एक बेटा हुआ और उसके बाद उन्होंने 2017 में तलाक ले लिया। इसके बाद मलाइका अर्जुन कपूर के साथ रिश्ते में आ गई थीं, उनका यह रिलेशन काफी साल चला और अब फिर से वो अलग हो गए हैं। अब फिर से इस वीडियो के बाद मलाइका की लव लाइफ में एंट्री होती हुई नजर आ रही हैं।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक नरेश पी. बजाज द्वारा बैरक नंबर 887/27 सेक्शन 18, उल्हासनगर -421 003, जिला ठाणे से प्रकाशित व सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, आमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट, सोनवाला क्रॉस रोड -2, जवाहरनगर के पास, फाटक पुल, गोरेगांव, मुंबई -63, (महाराष्ट्र) से मुद्रित।
दूरध्वनि: 0251- 3238100, **कार्यकारी संपादक:** पंजू बजाज (पी. आर. बी. एक्ट के तहत कंटेट चयन के लिए जिम्मेदार) न्याय क्षेत्र ठाणे जिला। **hindmatamirror1@gmail.com** RNI. NO. MAHHIN/2011/43060 **स्थानीय संपादक:** शिवप्रताप